A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 13 जून, 2024

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 236, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

यूपी में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन, जिम्मेदार कौन ?

नितिन श्रीवास्तव

पिछले हफ़्ते, 3 जून को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह तड़के सुबह उठकर, तैयार होकर, आवास के बगल में बने शक्तिपीठ मंदिर में पूजा करके वापस लौटे। अपने लाल कक्ष से गुज़रते समय एक पुराने कर्मचारी ने पूछा, 'महाराज जी, कल आम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उसके अगले दिन आपका जन्मदिन भी है। आपके दर्शन उसके बाद होंगे?'

योगी आदित्यनाथ सिर्फ़ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ दिन कितने 'चुनौतीपूर्ण' होने वाले हैं। चार जून के नतीजों ने तो सबको चौंका दिया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं और भाजपा अपने बूते इस आँकड़े तक पहुंचने से 32 सीटें पीछे रह गई। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से अधिक सीटों की उम्मीद थी लेकिन पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी ने उससे अधिक सीटें जीत लीं, जबकि बीजेपी को मात्र 33 सीटों से संतोष करना पड़ा।

भाजपा-एनडीए गठबंधन को मिली 36 सीटें और कांग्रेस-समाजवादी पार्टी वाले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की झोली में आई 43 सीटें। भाजपा के लिए ये करारा झटका था क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए के पास 64 सीटें थीं।

योगी आदित्यनाथ के सर पिछली लोकसभा और पिछली विधानसभा चुनावों में जीत का सेहरा बँध चुका था लेकिन नतीजे ने उन्हें भीतर से झझकोर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 37 और कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें जितवा कर योगी को पछाड़ दिया है।

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के मुताबिक़, 'मोदी की केंद्र सरकार से ज़्यादा भाजपा की राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सीधे तौर से निशाना बनाया और ख़ासतौर से यूपी में जहां बुलडोज़र एक सरकारी प्रतीक बन गया। नए राम मंदिर वाले प्रदेश में 'हिंदुत्व की राजनीति' को सबसे करारा झटका लगा और जिस सपा पर भाजपा मुस्लिम-परस्त होने का आरोप लगाती रही है, उसी ने बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले प्रदेश में सपा को कहीं ज़्यादा वोट मिले। बीजेपी जिन सीटों पर हारी उनमें अयोध्या (फैज़ाबाद) भी शामिल है।' 2019 के आम चुनावों में यूपी में भाजपा को 49.6 प्रतिशत वोट मिले थे जो 2024 में गिर कर 41.4 प्रतिशत पर आ चुका है। दूसरी हक़ीक़त ये भी है एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार भी बन चुकी है और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

लखनऊ के हज़रतगंज स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय का मंज़र 2014 से ही बदला हुआ है। चंद वर्षों में इस नए दफ़्तर ने योगी आदित्यनाथ को नया मुख्यमंत्री बनते भी देखा। गोरखपुर में राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर महेंद्र कुमार सिंह को लगता है, 'इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा फ़ैक्टर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी और भाजपा के ग्रासरूट कार्यकर्ता का घटा हुआ, मनोबल क्योंकि ज़्यादातर ने पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ख़ुद को अलग-थलग महसूस किया।' इस चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दफ़ा अपने भाषणों में 'अपराधियों और गलती करने वालों पर बुलडोज़र के इस्तेमाल' की बात दोहराई थी। साफ़ है कि मतदाताओं ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही किसी के घर या ठिकाने पर बुलडोज़र के ज़रिए बल प्रयोग की नीति को नकार दिया है। यूपी चुनावों को कई दफ़ा कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार निधि राज़दान के मुताबिक़, 'अबकी बार 400 पार और मोदी की गारंटी वाले माहौल में यूपी में आरएसएस कैडर ने अपने को अलग-थलग महसूस किया। टिकट वितरण में स्थानीय लीडरशिप से ज़्यादा केंद्रीय लीडरशिप का रोल दिखा जो उल्टा साबित हुआ। इस तरह की भी अपुष्ट खबरें आती रहीं कि आगे चलकर भाजपा योगी को बदल भी सकती है जबकि ख़ुद योगी और पीएम भाषणों में बुलडोज़र की बातें दोहरा रहे थे।' स्थानीय मीडिया में आम नैरेटिव यही चलाया जा रहा था कि 'कड़क मुख्यमंत्री' योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से ज़्यादातर लोग खुश हैं।

उत्तर प्रदेश का लंबा दौरा करके लौटने वाली वरिष्ठ पत्रकार सबा नक़वी को लगता है, 'किसी न किसी पर तो ब्लेम आना ही था। दबे स्वर में सही लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ को यूपी में ख़राब प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार बताया जा रहा है।' भाजपा के एक दलित नेता ने बताया कि यूपी की 80 सीटों में से कम-से-कम 25 सीटों पर उम्मीदवार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने चुने, जबकि योगी किसी और को लड़ाना चाहते थे। अखिलेश यादव ने इस बार कैंडिडेट सेलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया और टिकट बाँटने में चाणक्य वाली भूमिका निभाई।' विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने अपने कई 'क़रीबियों' को भी मना करते हुए कुछ टिकट ऐसे दिए जो तुरुप का पत्ता साबित हुए। सपा के अखिलेश यादव का सिर्फ़ पांच यादव कैंडिडेट को टिकट देना-या फिर सिर्फ़ पांच-छह मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना इस बात का साफ़ इशारा है कि वे अपनी गणित बैठाकर ही मैदान में उतरे थे। यानी इंडिया ब्लॉक ने ओबीसी-दलित कार्ड को जितनी बेहतरीन तरीक़े से खेला, उसे भाजपा ने समझने में देर कर दी।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने बताया, 'विपक्ष लोगों को ये बताने में लगा रहा कि अगर भाजपा सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, एक नए भारत का निर्माण होगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको पहले चरण के मतदान में ही पकड़ने की ज़रूरत थी लेकिन हुआ उसके उलट।' चार जून की शाम तक पता चल चुका था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पर लोगों ने कम भरोसा दिखाया है, राम मंदिर निर्माण और हज़ारों करोड़ रुपयों के साथ अयोध्या के नवीनीकरण और बुलडोज़र से न्याय दिलवाने जैसे दावों ने बड़ी छाप नहीं छोड़ी है। जानकारों के मुताबिक़, यूपी के युवाओं में इस बात को लेकर रोष है कि निचले स्तर की सरकारी भर्तियाँ टलती रहीं और सरकार ने मुफ़्त राशन और फ्री गैस जैसी स्कीमों पर ज़्यादा ध्यान दिया।

चुनावी नतीजों से ये साफ़ हो चुका है कि इंडिया ब्लॉक को जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बाँटने का फ़ायदा मिला, साथ ही युवा वर्ग ने भी उन्हें ज़्यादा वोट दिया। फिर भी अहम मुद्दा यही बना हुआ है कि इसमें योगी आदित्यनाथ को क्या कांग्रेस-सपा ने झटका दिया या फिर किसी और ने ?

(बीबीसी हिन्दी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

कुवैत की बिल्डिंग में भीषण आग

40 भारतीयों की मौत

कुवैत सिटी (एजेंसी)। कुवैत के मंगाफ शहर की एक इमारत में आग लग गई। इसमें 40 भारतीयों के मरने की खबर है। इनमें 5 केरल के रहने वाले थे। हादसे में 30 भारतीयों समेत 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि अब तक 40 भारतीयों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे में 30 भारतीयों के जख्मी होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय राजदूत ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है।

● 5 केरल के, 30 भारतीय जख्मी ● इमारत में 160 मजदूर रहते थे

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के समयानुसार ये हादसा आज सुबह करीब 6 बजे हुआ। सुबह ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में 160 से ज्यादा लोग रह रहे थे। गृह मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ ने बताया कि इमारत में कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इसलिए अभी मरने वालों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पोस्ट में कहा, कुवैत में हुए हादसे से स्तब्ध हूं। वहां करीब 40 लोगों की मौत हुई है। हम डीटेल्स सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर संवेदना जाहिर की है।

दो दशक पुराना संबंध और प्रशासनिक दक्षता का संगम

मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, अब इस सवाल का काफी हद तक जवाब मिल गया है। डॉ. राजेश राजौरा इस कतार में सबसे आगे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी कार्यशैली और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उनके 20 साल पुराने संबंध, जो 2004 से सिंहस्थ के समय बने थे। आज ये दोनों अलग-अलग भूमिकाओं में प्रदेश की दो बड़ी कुर्सियों पर विराजित हैं।

- हेमंत पाल
(संपादक, 'सुबह सवेरे' इंदौर)

सरकार किसी भी पार्टी की हो और मुख्यमंत्री कोई भी हो, कुछ अफसर हमेशा चहेते बने रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता उनसे मेल खाती है। बल्कि, इसलिए उन्हें पसंद किया जाता है कि उनकी काम करने की शैली कुछ ऐसी होती है, जो हर मुख्यमंत्री को रास आती है। याद कीजिए जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जो पहली फाइल पर दस्तखत किए वो डॉ. राजेश राजौरा ने उनके सामने रखी थी, जिसमें धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर निकाले जाने संबंधी आदेश था। इससे पहले जब 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी, तब भी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी संबंधित जो आदेश जारी किया, वो फाइल भी डॉ राजेश राजौरा ने ही उनके सामने रखी थी।

याद किया जाए तो 18 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के भी वे चहेते अफसरों में एक थे। इन घटनाओं का जिक्र ही उनकी कार्यशैली दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भी उनके संबंधों का इतिहास 20 साल पुराना है। तब स्थितियां अलग थी, आज अलग है। किंतु कहीं न कहीं दोनों के बीच संबंधों का जो अंकुरण उस समय हुआ था, वो आज लहलहाता वृक्ष बन चुका है। अब वे मुख्यमंत्री के एसीएस बनाए गए हैं।

डॉ. राजेश राजौरा को सभी परिस्थितियों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। फिर वो उज्जैन का 2004 का सिंहस्थ हो (जब वे वहां कलेक्टर रहे) या आदिवासी जिला झाबुआ जहां वे जिला पंचायत के सीईओ रहे। फिर धार कलेक्टर के रूप में उन्होंने सफल कार्य किया, जिसकी आज भी चर्चा होती है। किसी कलेक्टर के लिए यह बड़ी उपलब्धि होती है कि उनके पद से हटने के बाद भी उनका जिक्र अच्छे संदर्भों में ज्यादा होता है। इंदौर जैसे बड़े जिले में बड़े ओहदे पर रहे डॉ राजेश राजौरा ने शहर में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने बरसों से रुके कई फैसलों को गति दी। इसमें एक एलआईजी और रिंग रोड के बीच का लिंक रोड भी है जो कई सालों से इसलिए नहीं बन पा रहा था कि रास्ते मे एक प्रभावशाली नेता कि बहन का मकान आ रहा था और उसे हटाना प्रशासन के लिए मुश्किल काम था। पर, अपने चातुर्य से डॉ राजौरा ने उसे हटवाया और आज ये लिंक रोड शहर के ट्रैफिक को आसान बना रहा है।

इसे संयोग ही माना जाना चाहिए कि 2004 में जब राजौरा उज्जैन कलेक्टर थे, तभी वहां सिंहस्थ का आयोजन हुआ था। उस सिंहस्थ की समिति में डॉ. मोहन यादव भी शामिल थे। उस समय दोनों के संबंधों की बुनियाद पड़ी। तब न तो डॉ. राजौरा को मालूम था और न डॉ. यादव को कि एक दिन दोनों अलग-अलग भूमिकाओं में इस ऊंचाई पर मिलेंगे। दोनों के संबंधों की जो शुरुआत 20 साल पहले पड़ी थी, आज वो बीज वटवृक्ष बन गया। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉ. राजेश राजौरा को अपने विश्वस्त अफसरों में मानते हैं और इसलिए उन्होंने यह अवसर दिया।

यदि कोई अफसर अपने गृह प्रदेश में ही मुख्य सचिव की कुर्सी तक पहुंचे, तो उसके काम करने का तरीका और सोच दूसरे अफसरों से अलग होती है। क्योंकि, उस अफसर की प्रदेश के प्रति आत्मीयता और काम के प्रति ललक कुछ अलग ही होती है। यह शुभ संकेत है कि केएस शर्मा के बाद डॉ. राजेश राजौरा भी मूलतः मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। केएस शर्मा का प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल 31 जनवरी 1997 से 31 जुलाई 2001 तक रहा। वे होशंगाबाद के रहने वाले हैं। अब अगर राजौरा मुख्य सचिव बनते है तो वे केएस शर्मा के बाद दूसरे मुख्य सचिव होंगे जो मध्य प्रदेश के निवासी है। डॉ राजौरा मूलतः नीमच के रहने वाले हैं।

पेशे से डॉक्टर इस अफसर ने एम्स (दिल्ली) से एमबीबीएस किया है। यही वजह है कि स्वास्थ्य को लेकर उनमें अतिरिक्त सजगता है। उनकी काम करने की शैली का एक प्लस पॉइंट उनकी सहजता को भी गिना जा सकता है। वे जिस भी जिले में कलेक्टर रहे, उन्हें चाहने वालों की एक लंबी फौज खड़ी हो गई। क्योंकि, उन्होंने जनता और खुद के बीच कभी कोई सीमा रेखा नहीं खींची। उनके दफ्तर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद हुए हों, ऐसा न कभी दिखाई दिया और न सुना गया। उनकी एक खासियत यह भी है कि उनके चेहरे के भाव देखकर कभी उनके मन की बात को पढ़ना आसान नहीं है। शायद ही कभी किसी ने उन्हें गुस्से में देखा होगा। यही उनकी सहजता भी है। अपनी प्रशासनिक दक्षता से वे हमेशा सीढियां चढ़ते रहे और अब वे उन पायदान से एक कदम पीछे है जहां पहुंचना हर आईएएस अफसर का सपना होता है।

यहां उनका यह जिक्र इसलिए कि अपनी बेहतरीन प्रशासनिक कार्यशैली की वजह से 1990 बैच के इस आईएएस अधिकारी को अगला मुख्य सचिव बनाए जाने का रास्ता मंगलवार को साफ हो गया। नए फेरबदल में उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ मुख्यमंत्री का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। समझा जाता है कि इस पद का दूसरा सिरा चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर खुलता है। मुख्यमंत्री के एसीएस के साथ वे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विभाग के अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे। संभव है कि राजौरा की नियुक्ति में क्षिप्रा शुद्धिकरण के मकसद से की गई हो? मंत्रालय में ये तीनों विभाग काफी भारी-भरकम माने जाते हैं।

वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विश्वस्त अफसरों में माने जाते हैं। क्योंकि, सीएम ने उन्हें 22 दिसंबर को अपने गृहनगर उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया। उन्हें संभागीय स्तर पर विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए भी उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है। सरकार के इन सारे फैसलों को देखते हुए समझा जा सकता है कि वे उनके प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी बनने में अब कोई अड़चन नहीं है। यही कह सकते है कि प्रदेश का अगला मुख्य सचिव वही अधिकारी बन सकता है, जो मुख्यमंत्री के काम करने के ढांचे में अपनी प्रशासनिक दक्षता से फिट बैठता हो। वह कुशल प्रशासक के साथ मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के इशारे को भी समझता हो और डॉ राजेश राजौरा की कार्यशैली उन्हें इसमें सिद्धहस्त साबित करती है।

सुप्रभात

मेरे प्राणों में

तुम्हारे प्राण हैं

मेरे हृदय में
तुम्हारी नदी बहती है

मेरे पैरों में
तुम्हारी गति है

मेरे गीतों में
तुम्हारे स्वर हैं

मेरी कविता में
तुम्हारे छंद हैं

तुम मुझमें हो
तुम हो तो
मैं हूँ।

- दुर्गाप्रसाद झाला

पानी बचाने और जल स्त्रोत सहेजने के काम में लगे समाजसेवियों को करें सम्मानित : सीएम डॉ. यादव

- **विभिन्न जिलों में हुए अच्छे कार्यों और नवाचारों की हुई प्रशंसा**
- **वीडियो कॉन्फ्रेंस में दी गई जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों की जानकारी**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने गत 6 माह में जनकल्याण के अनेक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करेगा। हम विकास की नई इबारत लिखेंगे। विकास की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को भी शामिल होकर बेहतर परिणाम लाने में सहयोग करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सांसद, विधायक, मंत्रीगण, जिलों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और अधिकारीगण वीडियो कांफ्रेंस में उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी विभिन्न स्थानों से वीडियो कांफ्रेंस में शामिल हुए। जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेंस में कहा कि ऐसे समाजसेवी जिन्होंने अभियान में आगे बढ़कर हिस्सेदारी की है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे अन्य लोग भी ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित हों। ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाए।

जिलों में सम्पन्न गतिविधियाँ

गत 5 जून से प्रदेश में प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मंडला जिले में जिले की आबादी के बराबर 11.5 लाख पौधे रोपने की पहल की गई है। मनरेगा के अंतर्गत जो 5 हजार कार्य चल रहे हैं, उनमें लगभग एक हजार ऐसे कार्य चिन्हित किए गए हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हैं। करीब 500 चेकडेम वन विभाग की ओर से निर्मित हो रहे, जिनकी लागत डेढ़ करोड़ रूपए है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर में तालाबों के पास पूजन सामग्री आदि के विसर्जन के लिए अलग स्थान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गढ़ा एवं अन्य क्षेत्र का मैंने सोमवार को निरीक्षण भी किया। वीरांगना रानी दुर्गावती के इस क्षेत्र में जल संरक्षण का बेहतर कार्य हो रहा है। यह कार्य सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे दानदाताओं की जानकारी भी सामने आना चाहिए। सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र में महाविद्यालय के लिए ढाई करोड़ रुपए का गुप्त दान देने वाले सज्जन को भी सम्मानित किया जाए।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 42.5 °c | न्यूनतम 36°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 13 जून 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या, और सख्त होगी सुरक्षा

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में यूपीएटीएस और एएसएफ की यूनिट के बाद अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) का हब बनेगा। एनएसजी का यह देश में छठवां हब होगा। अभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के रीजनल हब हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी को देखते हुए यह फैसला लिया है। जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। जमीन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। श्रीराम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्सस्त्र के हाथों है। मंदिर की सुरक्षा में 200 जवान तैनात हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में एटीएस और पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएसएफ का गठन किया है। 14 दिन पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली थी। पहले एक आईडी से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई। फिर 112 पर कॉल आई। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। साइबर एक्सपर्ट और सर्विलांस टीम को तुरंत ऐक्टिव किया।

राम मंदिर के पास होगा बेस पॉइंट, आतंकी हमले की आशंका और सुरक्षा को लेकर फैसला

संक्षिप्त समाचार

मोदी के पीएम बनने पर जिनपिंग ने साधी चुप्पी

- घिरे तो चीनी दूतावास के बदले सुर, गलती पर पर्दा डालने को दी सफाई

बीजिंग (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी ने इस रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर नरेंद्र मोदी को दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी है। वहीं भारत के पड़ोसी चीन की सत्ता में सर्वेसर्वा शी जिनपिंग ने चुप्पी साधे रखी। शी जिनपिंग की ओर से मोदी को बधाई नहीं दिए जाने की चीन और भारत में ही नहीं कई देशों की मीडिया में चर्चा हुई। इसे दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों को और खराब करने की तरह से देखा गया। आलोचना होने पर चीन की ओर से सफाई दी गई कि जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली है।

लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख

- 30 जून को पदभार संभालेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मंगलवार 11 जून की रात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। वे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति में सरकार ने सीनियॉरिटी के सिद्धांत का पालन किया है।

भारत बोला-

भारतीयों की सेना में भर्ती बंद करे रूस

- कहा-यह दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूक्रेन जंग के बीच रूस की सेना में तैनात 2 और भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भारत ने कहा है कि रूस हर हाल में अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करना बंद करे। यह दोनों देशों की पार्टनरशिप के लिए सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मॉस्को में भारतीय दूतावास ने दोनों भारतीय नागरिकों के शवों को जल्द से जल्द स्वदेश वापस लाने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय समेत रूसी अधिकारियों पर दबाव डाला है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख जताया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को भी रूस में नौकरी का ऑफर मिलने पर सावधानी बरतने की अपील की है।

5 घंटे में बुझी विदिशा की पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री की आग

- 15 फायर ब्रिगेड बुझाने में जुटी थीं, जहरीला धुआं फैलने से इलाके को खाली कराया

विदिशा (नप्र)। विदिशा में बुधवार सुबह करीब 7 बजे यूनिकल पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे में काबू पा लिया गया। 9 शहरों की 15 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी थीं। इनमें केमिकल की आग बुझाने वाली फोम की फायर ब्रिगेड भी शामिल हैं। फैक्ट्री से उठने वाला धुआं 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। केमिकल के कारण जहरीला धुआं फैलने से इलाके को खाली करा दिया गया है। यूनिकल पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री पूर्व विधायक और भाजपा नेता शशांक भार्गव की है। ये शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। यूनिकल फैक्ट्री से ही लगी यूनाइटेड फैक्ट्री में भी बड़ी संख्या में ड्रमों में केमिकल रखा था, जिससे यहां भी आग फैलने का डर था। जेसीबी की मदद से बाउंड्रीवॉल तोड़कर यूनिटाइटेड फैक्ट्री से केमिकल के ड्रमों को बाहर निकाला गया। इस फैक्ट्री से तैयार माल की सप्लाई विदेशों तक होती है। सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स रखा हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

- **धुआं देखा तो सोचा कूड़ा जलाया होगा-** फैक्ट्री के पास रहने वाले शशांक जैन ने बताया, सुबह करीब 6.50 बजे मैं फैक्ट्री के पास से निकल रहा था तो वहां पीछे की तरफ से धुआं उठ रहा था। मुझे लगा किसी ने कूड़े में आग लगाई होगी, लेकिन ऊपर जाकर देखा तो आग भभक रही थी। इसके बाद फैक्ट्री मालिक को जानकारी दी।
- **प्रत्यक्षदर्शी बोला- केमिकल के कारण फैली आग-** प्रत्यक्षदर्शी गोलू शर्मा ने बताया, आग से फैक्ट्री में रखी केमिकल की टंकियों में ब्लास्ट होने लगे। केमिकल के कारण आग फैलती जा रही थी।

ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने मोहन माझी, ली शपथ

शपथ लेने के बाद मांझी ने पीएम मोदी से लिया आशीर्वाद

केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने ली डिप्टी सीएम की शपथ

भुवनेश्वर (एजेंसी)। एक दिन पहले बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए मोहन माझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोहन माझी ने एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल रघुवर दास ने शपथ दिलाई। बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में अपने बूते पर जीत हासिल करते हुए बहुमत हासिल किया है। राज्य में मोहन माझी की सरकार में दो डिप्टी सीएम भी होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केवी सिंह देव और पार्वती परीदा ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर अपने बूते पर बहुमत हासिल किया है। राज्य में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद परिवर्तन हुआ है। इसके बाद नवीन पटनायक की विदाई हुई है। अभी इतने सालों तक बीजेडी सत्ता में थी। माझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। इनमें सुरेश पुजारी, रबिनारायण नाइक, नित्यानंद गोंड, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, मुकेश महालिंग, बिभूति भूषण जेना, कृष्ण चंद्र महापात्रा, गणेश राम सिंह खुंटिया, सूर्यवंशी सूरज, प्रदीप बालसामंता, गोकुला नंद मल्लिक और संपद कुमार स्वैन शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़,एमपी,असम, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड के सीएम मौजूद थे।

तैयार रहिए, हम आपके अफसर को सीधे जेल भेजेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने पानी पर हिमाचल, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया पर नकेल नहीं कसे जाने को लेकर बुधवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफिया पर नकेल नहीं कस पाती है तो हम दिल्ली पुलिस को लगाएंगे। शीर्ष अदालत ने पूछा कि हिमाचल से पानी आ रहा है तो ये दिल्ली में कहां जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर साफ-साफ जानकारी नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, तैयार रहिए, हम आपके अफसर को सीधे जेल भेजेंगे। कोर्ट ने संबंधित अफसर को गुरुवार को कोर्ट में पेश होने कहा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से गुरुवार तक हलफनामा देकर बताने को कहा है कि उसने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की वकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि उसने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। बेंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर भी नाराजगी जताई, जिसने एक पत्र में कहा था कि राज्य सरकार दिल्ली को जो 132 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ना चाहती थी, वह 'पहले से ही निर्बाध रूप से बह रहा है।' अदालत ने आश्चर्य जताया कि फिर राज्यों द्वारा पहले यह दावा करने का क्या मतलब था कि बैराजों पर अतिरिक्त पानी को मापा जा सकता है, ताकि पता चल सके कि कितना अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। जस्टिस मिश्रा ने पूछा, हिमाचल ने इस कोर्ट के सामने पेश किया कि हमारे पास अतिरिक्त पानी है। और अब पत्र में कहा गया है कि हमारे पास जो पानी है, वह पहले ही छोड़ा जा चुका है, इसका मतलब है कि उनके पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। आपकी (दिल्ली सरकार) याचिका का पूरा आधार यह है कि हिमाचल के पास अतिरिक्त पानी है, 137 क्यूसेक। फिर यदि आप इसे पहले ही छोड़ रहे हैं, तो हमारे आदेश के अनुसार जल बोर्ड की बैठक में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई।

चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने आंध्र प्रदेश के सीएम

- पवन कल्याण डिप्टी सीएम, टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने ली शपथ

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य की चौथी बार कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के एक मंत्री शामिल हैं। एक पद खाली रखा गया है। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू को गले लगाकर बधाई दी। नायडू के कैबिनेट में उनके बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, प्रदेश अध्यक्ष के. अत्चन्नायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नादेंडला मनोहर शामिल हैं।

चुनाव खत्म, अब सरकार की 100 दिन के एजेंडे पर नजर

शपथ लेने के अगले दिन से ही काम में जुट गए पीएम मोदी

मंत्रियों को थमाया 100 दिवसीय एजेंडा, सुझाव होंगे शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार का गठन हो गया और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। पीएम पद की शपथ लेने के अगले दिन से ही नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं।

दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस वक्त अपने 100 दिवसीय योजना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की समीक्षा कर रही है। जिससे कि हर मंत्रालय को उनका एजेंडा थमा दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट सचिव की देखरेख में नौकरशाहों और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 100 दिवसीय एजेंडा चुनाव की घोषणा के बाद तैयार किया गया था।

- विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सरकार स्टूडेंट्स से भी करेगी बात

भाजपा घोषणापत्र में शामिल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार जैसे कुछ प्रस्ताव भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुसार सभी मंत्रालयों के लिए विकसित भारत 2047 एजेंडा पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श किया जाएगा। यह विकसित भारत 2047 एजेंडा हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें से कुछ विचार बजट का हिस्सा बनेंगे। सरकार विकसित भारत लक्ष्यों को अंतिम रूप देने से पहले कॉलेज जाने वाले छात्रों और समाज के व्यापक वर्ग के विचारों को शामिल करना चाहती है। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र की प्राथमिकताओं को टारगेट किया है।

अखिलेश यादव ने करहल की विधायकी से दिया इस्तीफा

- कन्नौज के बने रहेंगे सांसद, नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ा

मैनपुरी/लखनऊ (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से शानदार जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने करहल सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल विधानसभा पर उपचुनाव कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शिवपाल यादव के नाम की चर्चा है। सपा प्रमुख यादव हालिया लोकसभा चुनाव में कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। विधानसभा में फिलहाल उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीत कर लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अखिलेश के अलावा फैजाबाद सीट से पहली बार सपा सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह मिल्कीपुर विधानसभा से सपा विधायक थे। वह 9 बार से विधायक चुने जा रहे थे। अवधेश प्रसाद यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव के बगल में बैठे नजर आते हैं।

इंदौर भाजपा नेता बम के कॉलेज पर 5 लाख जुर्माना

एमबीए पेपरलीक कांड पर फैसला, तीन 3 साल एग्जाम सेंटर भी नहीं बनेगा आयडलिक कॉलेज

इंदौर (नप्र)। इंदौर डीएवीवी के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लीक कांड पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट (कार्यपरिषद) ने फैसला ले लिया। दो प्राइवेट कॉलेजों पर अलग-अलग कार्रवाई होगी। भाजपा नेता अक्षय बम के आयडलिक कॉलेज पर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। यहां 3 साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा संघवी कॉलेज में गड़बड़ी मिलने पर इसे भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा। बैठक में पहली बार उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े भी भोपाल से इंदौर आए थे। उनकी मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि 25 मई और 28 मई को प्रस्तावित एमबीए के दोनों पेपर एक दिन पहले लीक हो गए थे। मामले में अक्षय बम के कॉलेज के ऑपरेटर का हाथ होने का खुलासा हुआ था।

संबद्धता या मान्यता पर फैसला जांच के बाद होगा- कार्यपरिषद बैठक के बाद सदस्यों ने जानकारी दी कि अक्षय बम के कॉलेज की संबद्धता/मान्यता रद्द करने की मांग उठी थी। अब संबंधित कॉलेज कैम्पस की जांच के बाद इस पर अलग से फैसला लिया जाएगा। कमेटी ने पाया है कि कॉलेज के स्तर पर लापरवाही हुई है। कॉलेज प्रिंसिपल भी इस संबंध में लिखित में जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को दे चुकी है।

चार पेज की रिपोर्ट में संघवी कॉलेज की गड़बड़ियों का भी जिक्र

जांच कमेटी की चार पेज की रिपोर्ट में आयडलिक के अलावा संघवी कॉलेज की लापरवाही भी सामने आई है। पेपर आउट होने के बाद संघवी कॉलेज से जब पुराने पेपर के बंडल मंगाए गए थे, तो उसमें छेड़छाड़ मिली थी। इसके चलते इस कॉलेज को भी अगले तीन साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है।

होटल में दूसरी लड़की के साथ था पति...

पत्नी ने पकड़ा, बोली- सास 6 लाख के दहेज के लिए भड़काती है...

इंदौर (नप्र)। इंदौर की राजेन्द्र नगर पुलिस ने बहू की शिकायत पर सास और पति पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक सास दहेज के लिए प्रताड़ित करती है और पति का दूसरी लड़की से अफेयर है। मैंने पति को उसके साथ होटल में पकड़ लिया। तब से पति जान से मारने की धमकी दे रहा है। राजेन्द्र नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक करिश्मा मनावरे निवासी अमर पैलेस कॉलोनी की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति अजय और सास उमा पर केस दर्ज किया है। करिश्मा ने अपनी एफआईआर में बताया कि उसकी शादी जनवरी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद सास उमा कहती थी कि वह कम दहेज लेकर आई है। इसके कारण कई बार परिवार के लोगों को भी ताने मारे। करिश्मा ने बताया कि वह जॉब के साथ घर का काम भी करती है। उसकी सैलरी सास अपने पास रख लेती है। सास उमा कहती कि बेटे की शादी में 6 लाख रुपए लगे हैं। वह पूरे पैसे चाहिए। जब भी पति अजय घर आते थे उन्हें भड़काती। इससे हम दोनों के बीच झगड़ा होता। पति मारपीट करते और हंगामा करते। एक दिन पता लगा कि पति अन्य लड़कियों से संपर्क में हैं। जब यह बात उनसे की तो उन्होंने कहा कि वह अब साथ में नही रखना चाहते। तुम मेरे किसी काम की नहीं और मारपीट की। करिश्मा ने 29 मई 2024 को अपने पति को एक लड़की के साथ होटल में पकड़ा। यहां पर अजय ने करिश्मा के साथ मारपीट कर दी। 31 मई को अजय का कॉल आया। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि घर से निकाल दूंगा। इस मामले में मामा का लड़का आयुष समझाने गया तो उसे भी पति ने जान से मारने की धमकी दी। सास भी परिवार की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इससे परेशान होकर करिश्मा ने थाने आकर मामले में केस दर्ज कराया है।

5 लाख दहेज के लिये सताया

आजाद नगर पुलिस ने ममता राव की शिकायत पर उसके पति सुनिल पुत्र पंडित राव के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2008 में हुई थी। शादी के बाद एक बेटा 13 साल ओर एक बेटी 9 साल है। 2018 से पति ने दहेज की बात पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पिता से 5 लाख रूपए लेकर आउ। लेकिन पिता की हालत खराब है। अब वह काम नही करते। भाई पर पूरा परिवार निर्भर है। यह बात पति को बताई तो उन्होंने मारपीट की ओर दोनो बच्चो को अपने पास रखकर घर से निकाल दिया।

इंदौर में 24 घंटे में 1 डिग्री उछला पारा

सुबह बादल छाने के बाद खिली धूप; शाम में बूंदाबांदी के आसार

इंदौर (नप्र)। इंदौर में पिछले 24 घंटे में दिन का तापमान करीब 1 डिग्री बढ़ा है। वहीं रात के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। एक हफ्ते पहले हल्की बूंदाबांदी के बाद से दिन का तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम का मिजाज ऐसा है कि रोज दोपहर बाद बादल छा रहे हैं और मौसम ठण्डा है। मंगलवार को दिन में पारा 1 डिग्री तक बढ़ गया जिस कारण उमसभरी गर्मी का भी असर दिखी। बुधवार सुबह से बादल छाने का बाद हल्की धूप खिली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर और आसपास के इलाकों में शाम को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इस दौरान 25-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके पहले मंगलवार को दिन का तापमान 36.6 (-1) और रात का तापमान 24.4(-1) रिकॉर्ड किया गया था। इसके पहले 8 जून को दिन का पारा 32.8 (-6) डिग्री सेल्सियस पर चला गया था। अभी जिस प्रकार से मौसम का रुख उससे हल्की बारिश के आसार हैं। दरअसल अभी प्री-

मानसून एक्टिविटी के चलते प्रदेश में दो तरह का मौसम है। कहीं आंधी-बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी का असर बना हुआ है।मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्री-मानसून एक्टिविटी है। दो दिन पहले मानसून महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा जिसमें अभी ठहराव है। हालांकि, अगले दो-तीन दिन तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ब्रांच थोड़ी कमजोर होगी। ऐसे में मानसून की 16-17 जून तक ही प्रदेश में इंट्री होगी।

बीजेपी विरोधी काम करने पर दो नेताओं पर कार्यवाही

इंदौर (नप्र)। बीजेपी ने अपने दो नेताओ पर अनुशास्तमक कार्यवाही करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है वह वरिष्ठ नेताओं की नसीहत के बाद भी क्षेत्रीय पार्षद को लेकर सोशल मीडिया पर टीका-टिप्पणी कर रहे थे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के शहर अध्यक्ष दिनेश वर्मा ने बताया कि छत्रसाल मंडल के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जरिया और मीडिया प्रभारी प्रहलाद चौहान को उनके पद से हटा दिया है। दोनों के ही खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यह पार्टी के विरोध में टिप्पणी करते हैं। वहीं दोनों ने ही विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने विधानसभा 5 में पार्टी के खिलाफ काम किया था। तब दोनों को ही नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। लेकिन नोटिस के बाद भी इनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां जारी रहीं तो नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे को जानकारी दी गई और उनकी सहमति के बाद इन्हें पदमुक्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पदाधिकारी भाजपा के पूर्व पार्षद के खास थे और वर्तमान पार्षद संगीता महेश जोशी को लेकर भी टीका-टिप्पणी किया करते थे। उनके बारे में स्थानीय बूथ अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी कार्रवाई के लिए लिखकर दिया था।

घर छोड़ा तो दोस्तों से कराया पत्नी का गैंगरेप

पति, सास-ननद सहित 6 को जेल भेजा, इंदौर में लव जिहाद का नया मामला

इंदौर (नप्र)। इंदौर के कनाडिया में महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और परिचितों से रेप कराने का नया मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति, सास और ननद सहित उनके परिचितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिकायत के बाद मंगलवार को पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। आरोपी पति शाहिद अहमद उर्फ राज, सास शबनम, ननद सानिया, ननद का दोस्त वसीम अख्तर और पति के दो दोस्त नौमान और फैजल खान पर केस किया है। सभी को मंगलवार शाम को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।महिला का दावा है कि बेटे को मारने की धमकी देकर पति ने दोस्तों और सास-ननद से अपनी करीबी से रेप कराया था। ससुराल वाले छह साल से प्रताड़ित कर रहे थे।

पीड़िता ने पुलिस को बताई आपबीती..

2019 में सबसे पहले कॉल सेंटर पर वह शाहिद से मिली थीं। तब शाहिद ने अपना नाम राज बताया। तब पता नहीं था कि वह किसी और धर्म का है। हमारी दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। शाहिद उर्फ राज ने मुझे शादी का भरोसा दिया इसलिए मैं मान गई। एक दिन जब शाहिद के घर खजराना पहुंची तो तब पता चला कि वह मुस्लिम है। मैंने कहा तुमने धोखा दिया। मैं हिंदू लड़की हूं, तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस पर शाहिद ने कहा कि वह अपने धर्म का त्याग कर देगा और हिंदू धर्म अपना लेगा। इस भरोसे में ही मैंने शादी कर ली। कुछ समय तक सब ठीक चला। गर्भवती हो गई। एक बेटा भी हुआ तो सब मुस्लिम नाम रखने की बात करने लगे। तब मैंने कहा कि तुमने कहा था कि धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ नहीं कहोगे। खुद भी हिंदू बनकर रहोगे तो बेटे को मुस्लिम नाम क्यों दिया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मेयर सख्त

इंदौर (नप्र)। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गर्म तेवर दिखाना शुरू कर दिए है। मामला है वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों के अनुबंध की अवधि बढ़ाने का है। इसमें पूर्व निगमायुक्त प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के अफसरों द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को धता बताया गया। इसके तहत एजेंसी का अनुबंध सात सालों के लिए बढ़ा दिया। खास बात यह कि मूल अनुबंध पूरा होने में तीन साल से अधिक का समय बाकी था। मेयर ने महापौर परिषद की शिकायत मिलते ही कलेक्टर को मामले की जांच कर गलत अनुबंध तत्काल निरस्त करने और दोषियों पर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। एजेंसी से बकाया वसूली के नोटिस भी जारी किए गए। इसके साथ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्लयू या लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। मूल अनुबंध की शर्तो पर ही एजेंसी को कोरोना अवधि के 22 महीने के साथ सात साल यानी करीब 9 सालों तक काम करने का ठेका बाले-बाले दे दिया गया।

लंदन विला डकैती का मास्टर माइंड सोमला पकड़ाया

इंदौर (नप्र)। बाणगंगा के लंदन विला डकैती कांड में जमानत के बाद फरार हुए डकैत सोमला को आलीराजपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। उस पर 40 हजार का इनाम घोषित था। इंदौर पुलिस जल्द उसे अभिरक्षा में लेगी। आलीराजपुर पुलिस ने लंदन विला डकैती कांड के मास्टर माइंड सोमला भील को बुधवार सुबह पकड़ लिया। सोमला अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचा था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया। सबूत के अभाव में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी लेकिन बाद में टीआई नीरज बिरथरे ने अपना पक्षा तो कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी। इसके बाद वह फरार हो गया था। तब से पुलिस सोमला को ढूंढ रही थी।आलीराजपुर पुलिस को भी एक मामले में सोमला की तलाश थी।

इंदौर में तीन थाना प्रभारी बदले

इंदौर (नप्र)। इंदौर में मंगलवार तीन थाना प्रभारियों के प्रभार बदल दिए गए। इस संबंध में मंगलवार शाम को आदेश जारी हुए। नई व्यवस्था के तहत खजराना में नए टीआई की पोस्टिंग हुई। वहीं द्वारकापुरी टीआई को अपराध शाखा भेजा गया। यहां पुलिस लाइन से नए टीआई की पोस्टिंग हुई है। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के आदेश पर खजराना में मनोज कुमार सेंधव की पोस्टिंग की गई है। यहां सट्टा कांड को लेकर पहले टीआई को हटाया जा चुका है। वहीं द्वारकापुरी टीआई अनिल गुप्ता को क्राइम ब्रांच भेजा गया है।

शादी के बाद पत्नी बोली...हाथ लगाया तो सुसाइड कर लूंगी

15 दिन बाद ही आईफोन, जेवर, नगद लेकर घर से भागी; केस दर्ज

इंदौर (नप्र)। इंदौर के विजयनगर में रहने वाले एक रिटायर्ड इंजीनियर ने अपनी बहू और समधी की पुलिस से शिकायत की है। इंजीनियर का आरोप है कि बहू और उसके पिता ने झूठ बोलकर शादी की। इतना ही नहीं बहू शादी के बाद घर के जेवर और अन्य सामान लेकर भाग गई। बहू को घर बुलाते हैं और फोन लगाते हैं तो वह धमका रही है। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की है। टीआई सीबी सिंह के मुताबिक सुनील चौकसे निवासी स्कीम नंबर 54 ने बहू मुस्कान और उसके पिता धर्मेंद्र राय पर केस दर्ज कराया है। सुनील ने बताया कि एक साल पहले शादी को लेकर उनकी चर्चा हुई थी।धर्मेंद्र ने अपनी बेटी का बयोडाटा भेजा। इसमें बताया कि बेटी मुस्कान ने बीएससी के साथ आईटीआई किया है। धर्मेंद्र ने खुद को शराब दुकान का सेल्समैन बताया। कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए शादी का खर्च नहीं उठा पाउंगा। सुनील ने कहा कि हमने धर्मेंद्र की हर बात मान ली। शादी के बाद से ही बहू मुस्कान बेटे से कई तरह की डिमांड करने लगी। उसने आभूषण मांगे। कुछ दिनों बाद वह सभी सामान और आईफोन लेकर अपने पिता के यहां चली गई। बेटे से कहा कि मुझे हाथ भी लगाया तो सुसाइड कर लेगी और पूरे परिवार को फंसा देगी। ससुर सुनील ने यह भी आरोप लगाया कि वह दूसरे लड़कों अपना रिश्तेदार बताते हुए बातें किया करती थी। इस मामले में पिता धर्मेंद्र राय को बात करने बुलाया तो वह शादी का 6 लाख खर्च मांगने लगे। इसके बाद सुनील ने पुलिस से शिकायत कर दी। जांच के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया।

इंदौर के परदेशीपुरा थाने से भागा रेप का आरोपी

धर्म परिवर्तन के प्रयास का भी आरोप था; हिंदू संगठन ने घेरा थाना

इंदौर (नप्र)। परदेशीपुरा थाने में बंद रेप का आरोपी मंगलवार रात मौका पाकर भाग गया। उस पर शादीशुदा महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। इसके विरोध में हिंदूवादी नेताओं ने बुधवार सुबह थाने का घेराव कर दिया है।

डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक फरार आरोपी का नाम राहुल उर्फ जफर है। उसके खिलाफ कुछ दिन पहले इलाके में रहने वाली शादीशुदा महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। आरोपी आजाद नगर का रहने वाला है। उसकी तलाश की जा रही है। इधर आरोपी पर एक ओर केस दर्ज किया गया है। वहीं थाने के स्टाफ से पूछताछ कर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।हिंदू संगठनों को भगाने के पीछे लापरवाही के अलावा साजिश का शक है। पुलिस ने आश्वासन दिया है।

ये था मामला

परदेशीपुरा पुलिस ने 28 साल की महिला की शिकायत पर राहुल उर्फ जफर के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और रेप की धाराओं में केस दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया था कि वह एक अस्पताल में काम करती थी। यहां फील्ड आफिसर के पद पर काम करने वाले अफसर ने अपना नाम राहुल बताया था। उसके पति शराब पीते थे तो अपनी बेटे-बेटी के साथ मां के पास रहती थी। अस्पताल में राहुल से दोस्ती हो गई। जून 2022 में राहुल घर आया। उसने जबरदस्ती संबंध बनाए। जुलाई मे पति की अचानक मौत हो गई। राहुल ने भरोसा दिलाया कि वह शादी कर लेगा बच्चों को अपना लेगा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए खजराना मंदिर में शादी कर ली। जनवरी में राहुल ने कहा कि तुमसे झूठ बोला मेरा असली नाम जफर शेख है। और मैं शादीशुदा हूं। फिर कहने लगा तुम मुस्लिम बन जाओगी तो मैं पहली पत्नी को तलाक दे दूंगा और तुम्हे साथ रखूंगा। इसके बाद आए दिन वह विवाद करने लगा। इसके बाद दोनों बच्चो को लेकर अलग रहने चली गई। यहां भी पता निकालकर आरोपी पहुंचा और विवाद करने लगा। बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। चचेरे भाई और रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंची और राहुल के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।

सिर में चोट से पिता की मौत, बेटा बोला- हत्या

मामा पर लगाया रंजिश रखने का आरोप, दो लोगों से पूछताछ शुरू

इंदौर (नप्र)। इंदौर के पास सिमरोल में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे का आरोप है कि हत्या उसके मामा ने की है। मेरी मां की मौत हो चुकी है। पिता इसके लिए मामा मेरे पिता को जिम्मेदार मानते थे। इसके चलते ही उन्होंने सुनियोजित तरीके से पिता की हत्या की है। बेटे के आरोप के बाद पुलिस ने मामा और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति मौत के कारण का पता चल सकेगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम गणेश (41) पुत्र गेंदालाल निवासी धार नाका महू रोड है। मंगलवार रात को उसके परिवार के लोग गणेश को लेकर अस्पताल पहुंचे। उसके सिर में चोट के निशान थे। यहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा है। इधर, अफसरों के मुताबिक

बेटे ने साले वीरेन्द्र निवासी हरसूद और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात तीनों ने शराब पी। इसके बाद गणेश नीचे गिर गया और सिर में चोट आई। इसी वजह से उसकी मौत हो गई।इस मामले में सिमरोल पुलिस का कहना है कि गणेश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

दोस्त का कॉल आया तब घर पहुंचा

गणेश के बेटे राहुल ने बताया कि उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। मामा सुबह उन्हें घर से लेकर गए थे। इसके बाद मृत हालत में उन्हें छोड़कर चले गए। बाद में उसे दोस्त ने बताया तब बेटा राहुल घर पहुंचा। राहुल ने आरोप लगाया कि उनकी मां की पहले मौत हो चुकी है। मामा वीरेन्द्र को शंका थी कि पिता ने उनकी हत्या की है। इसका बदला लेने के लिये मामा ने सुनियोजित तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा है।

बाइक चलाते समय आया हार्ट अटैक

इंदौर(नप्र)। इंदौर के कनाड़िया में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को बाइक पर बैठे-बैठे हार्ट अटैक आ गया। बताया जाता है कि रात में वह अपना काम निपटाकर घर लौट रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में अटैक आया। उन्होंने गाड़ी एक तरफ कर अपने साले को कॉल किया। साला उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कनाड़िया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिचौली मर्दाना में राधेश्याम (41) पुत्र शंकरलाल पटेल निवासी हुकुमचंद कॉलोनी की तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने अपने साले मयंक को कॉल किया। मयंक उन्हें देखने पहुंचा।

केदारनाथ यात्रा में इंदौर की युवती का हंगामा...

घायल मां को इलाज न मिलने का आरोप लगाया; इंदौरी बैंड का वीडियो भी हुआ था वायरल

इंदौर (नप्र)। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद तरह तरह के वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं। बुधवार को एक महिला के हंगामे का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में युवती खुद को इंदौर की रहने वाली बता रही है। केदारनाथ यात्रा में मां के साथ गई युवती ने मां के घायल होने पर इलाज न मिलने पर स्थानीय प्रशासन और डॉक्टरों पर आरोप लगा रही है। घायल मां को प्राथमिक इलाज न मिलने के कारण युवती ने हंगामा कर दिया। दरअसल युवती की मां बुजुर्ग होने के कारण पीठू से चढ़ाई कर रही थी। लेकिन पीठू का बैलेंस बिगड़ने के कारण महिला गिर गई। इस दौरान उनके हाथ और सिर में चोट आई। युवती का आरोप है कि पीठू को ले जाने वाला चालक भी उन्हें वहीं छोड़ कर भाग गया। साथ ही नजदीकी कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज की सुविधा न होने का हवाला देते हुए वापस ले जाने की बात कही। युवती का आरोप है कि उसके मां हार्ट पेशेंट है। डॉक्टरों को यह बताने के बात भी इलाज नहीं मिला, जिससे नाराज युवती ने हंगामा कर दिया।

कुछ दिन पहले इंदौरी बैंड का वीडियो वायरल हुआ था

केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान वहां इंदौर के युवा भी छाए रहे। इंदौर के 60 सदस्यीय दल ने कपाट खुलते ही ढोल की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। केदारनाथ में हनुमंत ध्वज पथक के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। 11 हजार 700 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड के बीच सबसे मुश्किल हालातों शिव के भजनों पर आधारित धुनों पर ढोल बजाए। सबसे ऊंची जगह पर ढोल ताशे बजाने का रिकॉर्ड बनाने वाले कलाकारों ने दूसरे वर्ष यह प्रस्तुति दी। पिछले वर्ष 40 कलाकारों ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। दल में 12 वर्ष से 35 वर्ष तक के कलाकार शामिल थे।

कपड़ा कारोबारी से लाखों की धोखाधड़ी

41 लाख से ज्यादा का कपड़ा लिया पर आधा पैसा ही दिया, केस दर्ज

इंदौर (नप्र)। इंदौर के राऊ थाने में होम फर्नीशिंग फैक्ट्री के मालिक ने खजराना के एक व्यापारी पर अमानत में खयानत का केस दर्ज कराया है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक लाखों का माल लेने के बाद व्यापारी ने आधे ही रुपए दिए। इसके बाद वह लगातार परेशान करता रहा। रुपए मांगने फैक्ट्री स्टाफ पहुंचा तो उन्हें आरोपी ने धमकी दी। इसके पीड़ित मालिक ने थाने आकर केस दर्ज करा दिया। राऊ पुलिस से मिली जानकारी क मुताबिक सत्येन्द्र यादव की शिकायत पर मोहसिन खान निवासी खजराना पर केस दर्ज किया है। सत्येन्द्र ने बताया कि उनकी राऊ में कैट रोड पर क्षितिजा इम्पेक के नाम से होम फनीर्शिंग कपड़े की फैक्ट्री है। मोहसिन खान एसके लिनेन के नाम से फर्म का संचालन करता है। व्यापारिक संबंधों के चलते 13 अक्टूबर 2023 को मोहसिन ने 41 लाख 62 हजार का माल खरीदा और 20 लाख 43 हजार का भुगतान कर दिया।

संपादकीय

ओडिशा में भी सोशल इंजीनियरिंग!

पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा में पहली बार शानदार जीत का परचम लहरा रही भाजपा ने वहां भी मुख्यमंत्री चयन व उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग का स्पष्ट संकेत दिया है। सीएम पद के लिए चर्चा में रहे तमाम चेहरों को दरकिनार कर ओडिशा में भी बिल्कुल नए चेहरे मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मांझी के साथ दो उपमुख्यमंत्री कनक वर्द्धन सिंहदेव तथा पार्वती परिदा भी बनाए जा रहे हैं। मांझी मंत्रिमंडल बुधवार को शपथ लेगा। मांझी के सीएम पद के लिए चयन का मुख्य आधार उनका समर्पित संघ कार्यकर्ता और मुखर राजनेता होना रहा है। मांझी राज्य की संथाल जनजाति से आते हैं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू भी इसी जनजाति से हैं। ओडिशा में आदिवासियों की आबादी करीब 23 फीसदी है। इसके पूर्व पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी विष्णु साय को सीएम बनाने के बाद भाजपा ने एक और आदिवासी को किसी राज्य की कमान सौंपी है। साय को सीएम बनाने का छग के आदिवासियों में सही संदेश गया और पार्टी वहां लोकसभा चुनाव में कुल 11 में से 10 सीटें जीत गई। ओडिशा में मांझी को सीएम बनाकर भाजपा ने पड़ोसी राज्य झारखंड में संदेश देने की कोशिश की है, जहां अभी झामुमो कांग्रेस गठबंधन सत्ता में है। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के रूप में अपना कॅरियर शुरू करने वाले मोहन चरण मांझी चार बार से भाजपा विधायक हैं। 52 वर्षीय मांझी 6वीं ओडिशा विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक थे। मांझी के नाम पर सहमति भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की आपसी चर्चा के बाद बनी। मांझी ने अपना राजनीतिक जीवन गांव के सरपंच पद का चुनाव जीतने से किया था। आज वह पूरे राज्य के 'सरपंच' बन गए हैं। गौरतलब है कि राज्य की राजनीति पर बारीक नब्ज रखने वाले मांझी के कहने पर ही भाजपा ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पूर्व में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल से कोई समझौता नहीं किया था। बीजेडी की अंतर्कलह और 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी बुरी तरह चुनाव हारी और भाजपा को विधानसभा चुनावों 147 में से 78 सीटों पर जीत हासिल हुई और लोकसभा की तो उसे एक भी सीट नहीं मिली। इन नतीजों के बाद बीजेडी में नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले पूर्व नौकरशाह वी.के.पंडियन ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। पटनागढ़ विधानसभा क्षेत्र से छह बार के विधायक केवी सिंहदेव और नीमापारा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार की विधायक पार्वती परिदा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। केवी सिंहदेव बोलांगीर के राजपरिवार से आते हैं और सवर्ण ठाकुर जाति से हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा तटीय ओडिशा से आती हैं और ओबीसी समाज से हैं। सिंहदेव भी सीएम पद की दौड़ में थे, जबकि पार्वती परिदा तो पहली बार ही विधायक बनकर उपमुख्यमंत्री बन गई है। भाजपा ने सिंहदेव के जरिए जहां ऊंची जातियों को साधा है, वहीं पार्वती परिदा के माध्यम से राज्य के उस महिला मतदाता वर्ग को संदेश देने की कोशिश की है, जो अभी तक बड़े पैमाने पर बीजेडी की समर्थक मानी जाती रही है। कुल मिलाकर भाजपा ने यह राजनीतिक संदेश देने की भरपूर कोशिश की है कि वह जातीय समरसता में भरोसा करती है, जो देश में हिंदू एकता के लिए जरूरी है। यह शायद पहली बार होगा कि जब देश के तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आदिवासी होंगे (पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दें)। यह आदिवासियों को समाज की मुख्यधारा में लाने तथा उनके हाथों में कमान देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिला है और आगे भी मिलेगा।

नजरिया

राम पुनियानी

लेखक आईआईटी मुंबई में शिक्षक रहे हैं और वर्ष 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मनी अवॉर्ड से सम्मानित हैं।

चुनाव के बाद अब पीएम मोदी के बयान का महत्व क्या?

बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, पेपर लीक, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को लेकर उनके दस साल के शासनकाल की आलोचना बढ़ती जा रही थी. इन महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, यह उनकी चिंता का मुख्य विषय था. महात्मा गांधी को लेकर इस तरह की बात कहने का उद्देश्य लोगों का ध्यान इन महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाने के साथ-साथ यह भी था कि नेहरू और पहले की कांग्रेस सरकारों को दुनिया को गांधीजी के बारे में न बताने के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सके.

एबीपी को 29 मई 2024 को दिए अपने एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''क्या पिछले 75 सालों में हमारी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि हम सारी दुनिया को महात्मा गांधी से परिचित करवाते? माफ कीजिये, मगर गांधीजी को कोई नहीं जानता था जब तक कि 1982 में उन पर बनी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी.' वे जब यह कह रहे थे तब उनका साक्षात्कार ले रहे एबीपी के प्रतिनिधियों के चेहरे भावशून्य थे. उन्होंने प्रधानमंत्री के इस सफेद झूठ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. इस अत्यंत लंबे चुनाव अभियान के अंतिम दौर में यह वक्तव्य दिए जाने के पीछे के उद्देश्य का अनुमान लगाना कठिन नहीं है.'

बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, पेपर लीक, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को लेकर उनके दस साल के शासनकाल की आलोचना बढ़ती जा रही थी. इन महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, यह उनकी चिंता का मुख्य विषय था. महात्मा गांधी को लेकर इस तरह की बात कहने का उद्देश्य लोगों का ध्यान इन महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाने के साथ-साथ यह भी था कि नेहरू और पहले की कांग्रेस सरकारों को दुनिया को गांधीजी के बारे में न बताने के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सके.

लेकिन इससे नेहरू और अन्य कांग्रेस सरकारें तो कटघरे में नहीं खड़ी होतीं, उल्टे गांधीजी के जीवन और उनके कार्यों, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा और उनके दुनिया के कई महान लोगों के प्रेरणास्त्रोत होने के बारे में मोदी कुछ नहीं जानते. इससे विश्व राजनीति पर 1930 के दशक से ही गांधीजी के असर के बारे में मोदी की अज्ञानता पता लगती है. गांधीजी को दुनिया रिचर्ड एटनबरो द्वारा लुई फिशर की गांधीजी की जीवनी पर आधारित फिल्म बनाए जाने के बहुत पहले जानती और मानती थी.

दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष की वजह से गांधीजी रंगभेद-विरोधी प्रमुख नेता के रूप में उभर चुके थे. गांधीजी के भारत वापस लौटने और किसानों के चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद उनके मित्र चार्ली एन्ड्रयूज ने चंपारण सत्याग्रह की अनूठी प्रकृति की बात सारी दुनिया में प्रचारित की. सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सत्याग्रह से कमजोरों और शोषितों की समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ.

बाद में उनके द्वारा छेड़े गए अन्य आंदोलनों - सविनय अवज्ञा एवं दांडी मार्च - को वैश्विक मीडिया में काफी कवरेज मिला. दुनिया में उनकी पहचान कायम होने से समाज की समस्याओं से साधारण जन को जुड़ने और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली. उनके कार्यों की खबरें और कथन बिजली की तेजी से सारी दुनिया में फैल गए. जहां एक ओर भारत में अंग्रेजों का दमन बढ़ता गया वहीं शांति, न्याय एवं अहिंसा जैसे मूल्यों का सम्मान करने वाले लोगों का ध्यान मानवतावाद के सिद्धांतों के सन्दर्भ में वैश्विक स्तर पर गांधीजी के योगदान की ओर गया.

शायद मोदी उस काल में गांधीजी के योगदान और दुनिया में उनके अत्यंत लोकप्रिय होने के बारे में न जानते हों, लेकिन उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि अंग्रेजी समाचार पत्र 'द बर्लिंगटन हॉक आई' ने रविवार, 20 सितंबर 1931 के अंक में पूरे एक पृष्ठ में उन पर सामग्री प्रकाशित की थी, जिसमें उन्हें 'विश्व का सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति' बताया गया था. प्रतिष्ठित अमरीकी पत्रिका 'टाइम' ने उनकी तस्वीर अपने मुखपृष्ठ पर प्रकाशित की और उन्हें सन् 1931 का 'मेन ऑफ द ईयर' घोषित किया. दो अन्य अवसरों पर उनकी तस्वीर इस प्रसिद्ध पत्रिका के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित की गई. इसी तरह टाइम की सहयोगी पत्रिका लाईफ ने भी गांधीजी पर केन्द्रित परिशिष्ट प्रकाशित किया.

दुनिया भर में अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से न्याय और शांति के लिए प्रयासरत लोग गांधीजी की ओर आकृष्ट हुए. महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आईंस्टाइन ने 1939 में लिखा 'मेरा मानना है कि गांधीजी के विचार हमारे दौर के सभी राजनीतिज्ञों में से सबसे अधिक प्रबुद्ध थे. हमें उनकी भावना के अनुसार काम करने का प्रयास करना चाहिए: अपने उद्देश्य के लिए लड़ाई में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज को आप बुरा मानते हैं उसमें भाग नहीं लेना चाहिए.' आइंस्टीन ने गांधीजी के बारे में लिखा, 'आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करेंगी कि रक्त और मज्जा का बना कोई ऐसा आदमी इस धरती पर रहा होगा.'

चार्ली चैपलिन भी गांधीजी के आन्दोलन से प्रेरित थे. वे गांधीजी से मिले और गांधीजी के मूल्यों का प्रतिबिम्ब चार्ली चैपलिन की फिल्मों 'मॉडर्न टाइम्स' और 'द ग्रेट डिक्टेटर' में दिखाई देता है. 'द ग्रेट डिक्टेटर' में वे गांधीजी और हिटलर के बीच विरोधाभास को दिखाते हैं. इसी तरह फ्रांसीसी नाटककार रोमां रोलां ने 'यंग इंडिया' के फ्रेंच संस्करण में लिखा, 'अगर ईसा मसीह शांति के राजकुमार थे, तो गाँधी भी इस उपाधि के लिए कोई कम योग्य नहीं हैं.'

बीसवीं सदी के दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला गांधीजी के संघर्ष से प्रेरित और प्रभावित थे और उन्होंने अपने संघर्ष के मार्ग का निर्धारण उसी आधार पर किया. सन 1959 में 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित अपने लेख में मार्टिन लूथर किंग ने लिखा, 'मुझे बहुत शुरू में ही समझ आ गया था कि गाँधी की अहिंसा की शिक्षा और ईसाई धर्म की प्रेम के शिक्षा का संश्लेषण ही नीग्रो लोगों के स्वतंत्रता और मानव गरिमा के लिए संघर्ष के सर्वश्रेष्ठ हथियार है.'

नेल्सन मंडेला के महान और लम्बे संघर्ष का आधार वे मूल्य थे जो उन्होंने गाँधीजी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से ग्रहण किये थे. उन्होंने महात्मा गाँधी की इस बात के लिए सराहना की कि उनमें 'नैतिकता और सदाचार का संगम तो था ही. इसके साथ-साथ वे दृढ संकल्प वाले व्यक्ति भी थे और उन्होंने कभी भारत के दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता नहीं किया.'

मोदी को यह पता होना चाहिए कि दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में 'गांधियन स्टडीज' पाठ्यक्रम का हिस्सा है. कई स्कूलों में गांधीजी की शिक्षाएं पढ़ाई जातीं हैं. दुनिया के करीब 80 शहरों में गाँधीजी के नाम पर सड़कें हैं और उनकी मूर्तियाँ हैं

जहां तक फिल्मों का सवाल है, हमारे अपने फिल्म्स डिवीज़न ने गांधीजी पर डाक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसका निर्माण विट्ठलभाई झवेरी ने किया था. यह फिल्म एटनबरो की फिल्म से बहुत पहले बनी थी. बल्कि एटनबरो ने यह फिल्म दो बार देखी थी और उन्होंने फिल्म के मुख्य पात्र बेन किंग्सले से कहा था कि गांधीजी के हावभाव और व्यवहार का तरीका समझने के लिए यह फिल्म देखें.

जहां तक मोदी के इस आरोप का सवाल है कि पुरानी सरकारों ने गांधीजी को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नहीं किया, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एटनबरो की फिल्म में भी भारत सरकार ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के ज़रिये एक बड़ी राशि निवेशित की थी. मोदी की जानकारी के लिए, एटनबरो की फिल्म को अन्यों के अतिरिक्त नेहरु को भी समर्पित किया गया है. नेहरु ने एटनबरो को यह सलाह दी थी कि वे अपनी फिल्म में गांधीजी को देवता न बनाएं बल्कि उनकी कमजोरियों के साथ एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करें. गांधीजी को लोग उन पर बनी फिल्मों के कारण नहीं जानते बल्कि उन पर फिल्में इसलिए बनीं क्योंकि उन्हें दुनिया जानती थी. उन पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गयीं हैं.

चुनाव खत्म हो गया है और गांधीजी पर यह बयान, जिसका उद्देश्य लोगों का ध्यान भटकाना है, का उपयोग हम राष्ट्रपिता और उनकी अमूल्य शिक्षाओं को एक बार फिर याद करने के लिए कर सकते हैं. सद्भाव और शांति की उनकी शिक्षाएं आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं.

अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया।

धर्म सम्मत राज्य- तानाशाही और पिछड़ेपन की पूरी संभावना

पुनर्पाठ

एल. एस. हरदेनिया

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

यह लेख 1993 में लिखा गया था। आज भी प्रासंगिक है।

भारत अपनी संस्कृति की प्राचीनता पर गर्व करता रहा है। संस्कृति का प्रवाह इतिहास की धारा मोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। संस्कृति की कोख से धर्म, राजनीति, सामाजिक परम्पराएं सब ही तो जन्म लेती रहती हैं। समाज के जीवनमरण के प्रश्न भी तो इन्ही में से उभरते हैं। संस्कृति को प्रत्येक युग की आवश्यकताओं की कसौटी पर कसकर परखने की आवश्यकता होती है। विगत शताब्दियों की सभ्यताओं ने अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिये संस्कृति से उन्हीं विचारों और परम्पराओं को चुना है जो वर्तमान को शक्ति दे सकें। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत भी सजगता के साथ इस स्वाभाविक प्रक्रिया को अपनाता रहा है। जिन देशों ने संस्कृति के उपयोगी अंश के चुनाव में गलती की, वे प्रगति की दौड़ में सैकड़ों वर्ष पीछे हो गए। राष्ट्रहित को धर्म, परम्परा, रूढ़ी, जाति आदि के व्यामोह से ऊपर उठकर अपना मार्ग निश्चित करना ही राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना है।

उपर्युक्त मानदण्ड से उन विश्व राष्ट्रों पर विचार करना उचित होगा जहां-'धर्म-सम्मत' राज्यों की स्थापना की गयी है। हमारे देश में भी उन राज्यों का उदाहरण देकर धर्म सम्मत राष्ट्र की कल्पना की जाती रही है और अब तो मांग के स्वर भी उभरने लगे हैं। इस बात पर राजनीतिक दलों के हित-अहित से ऊपर ऊठकर सोचने का आग्रह है।वर्तमान में विश्व में लगभग 200 आजाद राष्ट्र हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका अपना राजकीय धर्म है। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जहां धर्म की राजकीय मान्यता नाममात्र की है। वहां के राजनीतिक व प्रशासनिक जीवन में धर्म का कोई खास महत्व नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व का एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं जो प्रगति की प्रतियोगिता दौड़ में काफी आगे हो और जिसका अपना राजकीय मान्यता प्राप्त धर्म हो। इसके विपरीत जिन राष्ट्रों ने अपने यहां धर्म को राजकीय मान्यता दे रखी है उनमें से एक दो को छोड़ दें तो बाकी प्रत्येक दृष्टि से पिछड़े हैं। उनका पिछड़ापन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धरातल पर है। जिन देशों में धर्म को राजकीय मान्यता प्राप्त है या जिन देशों में अपने स्वयं के स्थापित धर्म हैं उनमें 24 ऐसे हैं जहां इस्लाम राज्यीय धर्म है। वे 24 राष्ट्र हैं- 1. अल्जीरिया, 2. बेहरेन, 3. अफगानिस्तान, 4 दी कमोरोम, 5. इजिप्त, 6 ईरान, 7. इराक, 8. जोर्डन, 9. कुवैत, 10. मलेशिया, 11. मालदोव, 12. मोरीटानिया 13. मारीशस, 14. मोरक्को, 15. ओमान, 16. पाकिस्तान, 17. कटार, 18. सऊदी अरेबिया, 19. सोमालिया, 20. सूडान, 21. ट्यूनीशिया, 22. यूनाईटेड अरब अमीरात, 23. नार्थ यमन, 24. साउथ यमन।

ग्यारह देश ऐसे हैं जहां रोमन कैथोलिक राजकीय धर्म है। वे देश हैं- 1. अर्जेंटीना, 2. कोलंबिया, 3. कास्टोरिका, 4. डोमोनिकल रिपब्लिक, 5. हेटी, 6. माल्टा, 7. पनामा, 8. पेराग्वे, 9. पेरू, 10. लेश चेलीज, 11. वेनेजुएला। चार देश ऐसे हैं जहां 'ईवेन्जेकोकल' लूथ्यरन चर्च धर्म हैं। वे हैं-डेनमार्क, आईलैंड, नार्वे और स्वीडन । तीन देशों में बुद्ध धर्म राजकीय धर्म है। वे देश हैं भूटान, कंबोडिया तथा थाईलैंड, ग्रीस में आरथोडाक्स चर्च को राजकीय धर्म की मान्यता दी गयी है। इजरायल में यहूदी और इंडोनेशिया में पंचशील शासकीय मान्यता प्राप्त धर्म है। पंचशील एक राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष विचार धारा है जिसमें एकता तथा सामाजिक न्याय पर काफी जोर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन देशों में रोमन कैथोलिक राजकीय धर्म है उनमें से अर्जेन्टाईना, कोलंबिया, पनामा, सेचेलीज और वेनजुएला ऐसे देश हैं जहां धर्म को अर्ध शासकीय मान्यता प्राप्त है। जिन देशों में धर्म को राजकीय मान्यता प्राप्त है उनमें से बहुसंख्यक दुनिया के सर्वाधिक पिछड़े देशों में हैं। यह पिछड़ापन भी बहुआयामी है। इन देशों की एक और विशेषता है। उनका शासन या तो अत्यधिक घटिया दर्जे के तानाशाह या राजशाही के हाथ में है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो कम ही देशों में है। साक्षरता के मामले में इन देशों की स्थिति ज्यादा पिछड़ेपन की है। इन देशों की आतंरिक स्थिति जानने के लिये हम उनमें से प्रायः सभी यहां की प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करेंगे ताकि उनके पिछड़ेपन का अंदाज हो सके। इनमें से अनेक ऐसे हैं जहां वर्षो से तानाशाही या आततायी किस्म की राजशाही है। इस तरह के राष्ट्रों में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें तानाशाही ने अपनी रक्षा के लिये अपने देश में धर्म को मान्यता दी है। अल्जीरिया को ही लें। अल्जीरिया फ्रांसीसी साम्राज्य से 1962 में आजाद हुआ। इसके बाद वहां अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुये और अंततः 1976 में अल्जीरिया को इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया।

बेहरिन-इस देश में इस्लाम को राजकीय मान्यता प्राप्त है। बेहरिन में मानव अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

ईरान-ईरान में इस्लाम को राजकीय मान्यता प्राप्त है। अयातुल्ला खौमेनी के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद ईरान पर कट्टरपंथियों का शासन स्थापित हो गया। ईरान में इस्लाम को वहां के संविधान से भी ज्यादा महत्व है। जैसे ईरान का राष्ट्रपति, वहां की असेम्बली भी धार्मिक आदेशों को मानने के लिये बाध्य है। वैसे नाम को वहां 16 राजनीतिक दल हैं परन्तु इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी का ही वहां बोलबाला है। इस पार्टी की स्थापना 1978 में इस्लामी क्रांति लाने के लिये हुई थी। प्राचीन देश होने के बावजूद ईरान में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 37 है। मानव अधिकारों के मामले में ईरान की स्थिति निंदनीय है। महिलाओं की स्थिति गुलामों जैसी है।

इराक-इराक में खाड़ी युद्ध का प्रमुख पात्र था, इस्लाम राजकीय धर्म है। वैसे सिद्धांत में इराक में अनेक राजनीतिक दल हैं परन्तु व्यवहार में वहां अरब बाथ सोशलिस्ट पार्टी ही का शासन है। इस पार्टी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता सद्दाम हुसैन थे, जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष भी रहे। इराक में सच पूछा जाये तो सद्दाम हुसैन की तानाशाही थी। यद्यपि वहां साक्षारता का प्रतिशत 43 है परन्तु वहां मानवाधिकार की सुरक्षा का प्रतिशत 19 ही है।

कोमोरोन-कोमोरोन एक छोटा देश है। यहां भी इस्लाम को राजकीय धर्म की मान्यता है। यहां भी एक पार्टी का तानाशाही राज है। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था प्रायः फ्रांस के इशारे पर चलती रही है। 62 प्रतिशत निवासी कृषि पर निर्भर हैं। बहुसंख्यक लोग निम्न आय श्रेणी में हैं। साक्षरता का प्रतिशत 48 है। मानव अधिकारों के बारे में किसी भी किस्म की जानकारी उपलब्ध नहीं।

मिस्त्र-वैसे नासर के नेतृत्व में मिस्त्र ने विश्व की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा की थी। परन्तु दुख की बात है कि वहां भी बाद के नेताओं को अपनी गद्दी बचाने के लिये इस्लाम का सहारा लेना पड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट के रूप में मिस्त्र की स्थापना 1922 में हुई थी। वहां साक्षरता का प्रतिशत 38 है। वहां के निवासियों को निम्न आय वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है। वहां की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रजातांत्रिक नहीं है।

जोर्डन-जोर्डन भी उन देशों में है जहां इस्लाम का बोलबाला है। इस देश की आबादी लगभग 35 लाख है। इतना छोटा देश होने के बावजूद यहां साक्षरता का प्रतिशत मात्र 6 है। यहां की शासन व्यवस्था सामंती है। यहां के राजा को संपूर्ण सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त है। इस देश के निवासी प्रायः गरीब हैं। 65 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित रिकार्ड पूरी तरह निराशाजनक हैं। जार्डन में राजनीतिक दल प्रतिबंधित है।

कुवैत-कुवैत में भी इस्लाम को राजकीय धर्म की मान्यता है। कुवैत की आबादी लगभग 17 लाख है। दूसरे अरब देशों की तुलना में कुवैत में साक्षरता का प्रतिशत अच्छा है।नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुवैत में साक्षरता का प्रतिशत 68 है। कुवैत के ऊपर एक परिवार का शासन है। प्रजातंत्र नाम की कोई चीज कुवैत में नहीं है। वहां राजनीतिक पार्टियां प्रतिबंधित हैं।

सोमालिया-सोमालिया एक अफ्रीकी देश है। इसकी आबादी लगभग 70 लाख है। सोमालिया में इस्लाम को राजकीय धर्म की मान्यता प्राप्त है। साक्षरता का प्रतिशत मात्र 6 है। 78 प्रतिशत निवासी कृषि पर निर्भर हैं। सोमालिया के निवासियों को निम्न आय श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था तानाशाही है। एक ही राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त है। मानव अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था अत्यधिक निराशाजनक है।

सूडान-सूडान भी एक अफ्रीकी देश है जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है जिसे निम्न आय वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है। साक्षरता का प्रतिशत 31 है। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था तानाशाही है। इस्लाम राजधर्म है। 1989 की सैनिक क्रांति के बाद सूडान में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मानव अधिकार पूरी तरह असुरक्षित है।

ट्यूनीशिया-ट्यूनीशिया की आबादी 70 लाख है। यहां भी इस्लाम को राजकीय मान्यता प्राप्त है। संभवतः ट्यूनीशिया दुनिया के उन देशों में सर्वाधिक बिरला होगा जहां 1975 में हबीब बोरजोबा को जीवन पर्यन्त राष्ट्रपति बना दिया था। यद्यपि उनके उत्तराधिकारी ने संविधान में संशोधन कर इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था इसके बावजूद अभी भी वहां प्रजातंत्र नाममात्र को है। 1989 के चुनाव में नेशनल असेम्बली की समस्त सीटों पर एक ही पार्टी का कब्जा हो गया था। उस समय आरोप लगाया गया था कि चुनाव में असीमित धांधलीबाजी की गयी थी।

अमीरात-यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे यू.ए.ई. भी कहते हैं का उदय एक संघीय राष्ट्र के रूप में 1991 में हुआ था। यह राष्ट्र छोटे क्षेत्रों के विलय से बना है। ई.एम.इ. का शासन तानाशाही है। यहां न तो राजनीतिक पार्टियां हैं व न ही चुनी हुई असेम्बली। इस्लाम को यहां भी राजधर्म का दर्जा हासिल है। वैसे साक्षरता का प्रतिशत 54 है। उपर्युक्त धर्म सम्मत तानाशाही की तरह ही मोरटानिया, मोरक्को, ओमान, कटार, सऊदी अरेबिया में भी कमोबेश यही स्थिति है। इन राष्टों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि जिन देशों ने धर्म को शासकीय मान्यता दी है उन्होंने पिछड़ेपन, तानाशाही व रूढ़िवादिता को आमंत्रित किया है। भारत की एकता, अखंडता, वैज्ञानिक विकास के लिये समन्वयमूलक संस्कृति ही उपयोगी है। आग्रह-दुराग्रह से हटकर, निष्पक्ष होकर, सम्पूर्ण राष्ट इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें।

कटाक्ष

रूपया खींचने के चक्कर में

-डॉ. एन. के. सोमानी

सुना था, रूपया रूपये को खींचता है। मैं नहीं मानता ! खींचा होगा कभी किसी के रूपये ने पर मेरे साथ हटकर हुआ..... ! हुआ भी ऐसा कि मैं खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। 'रूपया रूपये को खींचता है'। मैं इस आधार वाक्य की परीक्षा करना चाहता था। फिर क्या था रूपया खींचने के चक्कर में रूपया जेब में डालकर बीच बाजार आ गया...। उम्मीद थी कि मेरी जेब में पड़ा रूपया चारों दिशाओं से रूपये को खींच-खींचकर यहां जमा कर देगा और मैं आराम से पोटली बांधकर घर ले जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा रूपया कमजोर निकला। दूसरों को खींचने के चक्कर में जाने खुद किस दिशा में खींच गया पता ही नहीं चला। अब मैं यहां खड़ा हाथ मल रहा हूं। यह भी एक सुखद स्थिति हैं। इसका अहसास भी आज ही हुआ हैं । जब आदमी किसी के हाथों ठगता है तो अपनी झेंप मिटाने के लिए हाथ मलने लगता है। यही स्थिति मेरी थी। हाथ मलने के अलावा मैं अब कर भी क्या सकता हूं।बड़ा कष्ट हुआ। मन व्यथित है। पिछले सप्ताह से उस एक इकलौते रूपये को सहेज कर रखे हुए था। जाने कब काम आ जाए। आज वो भी बीच बाजार साथ छोड़ गया। कहां ढूंढू ? किसे पुकारू ? बड़ा निष्ठुर निकला ..... अवसान की इस वेला में साथ छोड गया ! हद्वय विहीन ! ! बड़ा नाजों से पाला था यूं सरे राह रूसवा कर जाएगा सोचा भी नहीं था। यूं दिल तोड़ कर जाने से पहले कुछ कहा होता या कोई शिकवा-शिकायत होती। कुछ गिला होता तो समझा बुझाकर मना लेता। हाय ! एक अंतिम झलक तक नहीं देख पाया.....स्पर्श के सुख से वंचित रह गया। ओ दुनिया के रखवाले....सुन दर्द भरे मेरे नाले.... !

सब व्यर्थ है, अब रोने से क्या फायदा....गलती मेरी ही थी। अर्थशास्त्र का 'अ' नहीं जानता और हिमाकत रूपया खींचने की कर रहा था। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कौन बक्शता। मात खा गया ! जब तक रूपया पास था अर्थशास्त्र के सिद्धांत करवट ले रहे थे अब रूपया गंवाकर दर्शनशास्त्री हो गया हूं। जेब भारी हो तो ज्ञान दबा रहता हैं। जेब खाली होते ही ज्ञान चक्षु चरमराकर खुलने लगते हैं। कल तक डॉलर और रूपये के बीच अंतर करता था अब रूपये -रूपये के बीच का अंतर जान गया हूं। मेरा रूपया भी मेरे लिखे हुए कि तरह। कमजोर साबित हुआ इस बात का अहसास आज हो गया है। मैं चाहकर भी पाठक नहीं खींच पाया और वह रूपया !

दरअसल, मैं जिस जगह खड़े होकर रूपया खींचने की जुगत भीड़ा रहा था वहां से एक मार्ग एक राष्ट्रीयकृत बैंक तक जा रहा था और दूसरा मार्ग एक प्रतिष्ठित फाईनेंस कंपनी की तरफ। दोनों की गिद्ध दृष्टि पिछले कुछ दिनों से मेरे रूपये पर लगी हुई थी आज मौका ताड़कर पार कर गए । जिस जगह से मैं रूपया खींचने का प्लान बना रहा था वहीं से एक तीसरा रास्ता एक बहुमंजली दूधिया रोशनी में नहाए हुए व्यवसायिक मॉल की तरफ जाता है... हो सकता है रूपया मेरी जेब से छिटककर उस दिशा में लुढ़क गया हो। चैथा रास्ता मल्टीपरपज कंपनी की तरफ भी जा रहा था क्या पता वह गुस्ताख मेरी जेब से निकलकर प्रबंधन का पाठ पढ़ने कंपनी के कैम्पस में चला गया हो। दिशाए चार है और मैं अकेला ! कैसे निकालू अपने इकलौते रूपये को इनके चंगुल से ! बड़ी भारी गलती हुई प्रभु ! मैं इन दिशाओं से आने वाली व्यवसायिक हवाओं को पहचान नहीं पाया और हवा मेरे रूपये को उड़ा ले गई। अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों को समझे बिना रूपया खींचने का अपराध किया....अब रूपया गंवाने की सजा भुगत रहा हूं।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पीठ खुजाइए सरकार !

अपने नए स्टाफ के साथ वे पहुंचे, बोले -'आपके समर्थन की वजह से सरकार बन गई है । अब हमारी कोशिश है कि कामकाज अच्छे से हो । बताइये कि सबसे पहले सरकार क्या करे ?' उन्होंने फूलों का गुच्छा हाथ में पकड़ाया और उतनी मुस्कान खेंची जितनी कि उनके पिछले राजनीतिक कार्यकाल में कभी नहीं खेंची थी ।

'यहाँ बैठिए और जरा मेरी पीठ खुजाइए तो । बड़ी खुजली चल रही है । सुना है आपके नाखून बहुत तेज हैं ।' समर्थन देने वाली पार्टी के बाबू-एक ने पीठ उनकी ओर करते हुए कहा।

'अरे !! ... बाबू पीठ तो आप अपने किसी चपरासी से खुजवा लीजिए ना । हमसे क्यों ! ... हम सरकार हैं !!'

'आप सरकार इसलिए हैं ... क्योंकि हम हैं । ... इतना मत सोचिए सरकार, फफटफट पीठ खुजाइए ।'

सरकार सोचने लगे कि गठबंधन राजनीति में सब करना पड़ता है यह तो सुना था लेकिन पीठ खुजाने के बारे में पहली बार पता चल रहा हैं ! डर मीडिया वालों का बहुत है । पता नहीं कहाँ कहाँ से देख लेते हैं ! कल अगर हेड लाइन बन गई कि सरकार ने समर्थन के बदले पीठ खुजाई तो एक दशक से प्रतिष्ठित नाखून बदनाम हो जाएंगे । बहुत सोच कर सरकार घिघियाए, --'देखिए बाबू ... मैं अपने पीए को कह देता हूँ वो आपकी पीठ खुजा देगा । अगर हमने खुजाई तो आप जानते हैं एक समर्थक दल और है । उसको भी खुजली चलने में देर नहीं लगेगी । ... आखिर सरकार को दूसरे काम भी करना हैं ।'

'पीए तो हमारे पास भी हैं जी । उसी से पीठ खुजवाना होती तो आपको समर्थन क्यों देते !!'

'लेकिन जरा सोचिए, जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा !'

'हम खुजवा रहे हैं तो मैसेज हमारे हक में ही जाएगा । लोगों को पता तो चले कि हमारी हैसियत क्या है, वरना सरकार तो आप हैं , जैकारे भी आपके लगने वाले हैं ।'

'तो बाबू ऐसा करते हैं ... यहाँ नहीं ... प्लीज अकेले में खुजवा लीजिए ... दूसरी पार्टी को पता चलेगा तो वो भी अपनी पीठ खोल के बैठ जाएगा ...'

'दूसरी पार्टी वाले पीठ नहीं खुजवाएंगे सरकार । उनका इरादा तो डायपर बदलवाने का है । ... उनके यहाँ गुड्डू, पप्पू, छोटू वगैरह हैं ... गठबंधन राजनीति में आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है । खुजाने और डायपर बदलने पर सरकार चलती है तो सौदा सस्ता है जी । आइए अपने नाखूनों का सदुपयोग कीजिए ।'

साक्षात्कार

डॉ. मनीष जैसल

साक्षात्कारकर्ता जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग आईटीएम विश्वविद्यालय, ग्वालियर में विभाग प्रमुख हैं।

सिनेमा में सामाजिक मूल्य फिल्मकारों की नैतिक जिम्मेदारी

प्रश्न- आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़े हैं, नाटकों की दुनिया से निकल फ़िल्मों में खुद को स्थापित किया है। नाटक और फ़िल्में लिखते समय किन संवैधानिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों की सीमाओं का ध्यान रखना होता है ?

नाटक की दुनिया थोड़ा ज़्यादा उदार लगती है मुझे । 25-30 साल पहले जो मैंने नाटक लिखा था बजे ढिंढोरा वो हास्य राजनैतिक व्यंग था, उस पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नही की । और तो और लोगों से उसे हाथों हाथ लिया खूब पसंद किया । राजनैतिक परिदृश्य जैसे जैसे विकसित हो रहा है संवैधानिक संकट बढ़ रहा है रचनाकारों पर, फ़िल्मकारों और नाटककारों पर। ऐसा होना नही चाहिए। छोटी छोटी बातों पर कब क्या तमाशा बन जाए आप जान नही पाएँगे । नाटक और फ़िल्म में कब कौन सी बात संवैधानिक महत्व की लगे कब वो असंवैधानिक हो जाए ये पता ही नहीं चलता । इससे रचना प्रक्रिया बाधित होने लगती है । 30 साल पहले ऐसी स्थिति नही थी । मैं तो कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण जी से काफ़ी प्रभावित भी रहा हूँ । उन्होंने अपनी विधा में मारक कार्टून के ज़रिए मुद्दे उठाए थे । गांधी, नेहरु, इंदिरा, अटल बिहारी आदि पर उनके कार्टून थे । बाद के वर्षों में कार्टूनिस्ट पर मुक़दमे होने लगे । देखते देखते चीज़ें बदल गयी है । एक डर का माहौल भी रचनाकारों के बीच बढ़ा हैं ।

प्रश्न- आप एक फ़िल्म लेखक हैं, आज़ादी के बाद के सिनेमा में हमें सामाजिक सरोकार वाली फ़िल्में देखने को मिलती है, और आज के सिनेमा के कथानक में बदलाव आ गया है । इसे आप कैसे देखते हैं?

पहले का सिनेमा जन सिनेमा होता था । सामाजिक सरोकार की फ़िल्में बहुत बनती थी। फ़िल्मकार बिना सरोकारके विषय वाली फ़िल्में बनाना पसंद भी नही करते थे। नया दौर, मज़दूर, सुजाता, बंदिनी,अछूत कन्या, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम, गरम हवा जैसी तमाम क्लासिकल फ़िल्में आपको देखने को मिल जाएगी।

फिर धीरे-धीरे सिनेमा मनोरंजन की ओर बढ़ने लगा। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं स्वस्थ मनोरंजन को बुरा नही मानता। कोई फ़िल्म सिर्फ़ ख़ालिस मनोरंजन भी दर्शकों को उपलब्ध कर दे तो भी फ़िल्मकार की ये बड़ी उपलब्धि है।

सिनेमा और रंगमंच ज़रूरत के हिसाब से कभी शिक्षक की भूमिका निभाता है, कभी जोकर बनकर मनोरंजन करता हैं कभी सुख दुःख बाँटने वाली कहानियाँ भी यही सिनेमा दिखाता है । लेकिन 15-20 सालों में जो सिनेमा बना है वो पैसा कमाने का ज़रिया बना है । संवैधानिक मूल्यों का हनन खुले आम हो रहा हैं । फ़िल्म में हम देखते हैं कोई भी पुलिस वाला किसी का भी एनकाउंटर कर सकता है । कोई भी विलेन पुलिस को वहीं ख़रीद सकता है । कोई आदमी किसी को भी कहीं भी मार सकता है । इसी का ही असर समाज में भी पड़ रहा है । किसी से बदला लेने के लिए न्याय व्यवस्था से ज़्यादा लोग खुद उसे मार कर फ़ैसला लेने की ओर आतुर दिखते हैं । क्योंकि फ़िल्म में भी यही दिखता है ।

प्रश्न- आपने वेलकम टू सज्जनपुर, बवंदर, समर जैसी अनेक फ़िल्में लिखी हैं। फ़िल्में लिखते समय क्या सेन्सरशिप नियम भी दिमाग़ में रहते हैं ? या फिर फ़िल्म बैन ने के बाद उसका सामना आपको करना पड़ा हो? क्या एक लेखक की रचनाशीलता को बाधित नही करता सेन्सरशिप?

वेलकम टू सज्जनपुर ने हाल ही में 15 साल पूरे किए हैं। उसमें तो मुझे ऐसा कोई संकट आया नही । श्याम बाबू ने उसे बहुत खूबसूरती से निर्देशित किया है। और ये बात यहाँ ज़रूरी है कि हमें पता था कि कौन सी बात

फ़िल्म में रखनी है जो संवैधानिक दायरे में रहेगी। इसीलिए आज तक उसमें कोई आपत्ति दर्ज नही हुई। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, उसके दायरे में रहने वाले फ़िल्मकार हैं इसलिए ऐसा कुछ हमारे सामने संकट नही आया। फ़िल्म में एक जगह दृश्य आता हैं जिसमें एक दलित लड़की पर मुखिया आरोप लगाता है उसको लेकर थोड़ा विरोध हुआ यूपी के किसी समाज के लोगों ने किया था। हमने तर्क दिया थे कि उच्च वर्ग का वो व्यक्ति दलित लड़की और उसके परिवार को फँसाने के लिए कैसे कैसे झूठ बोला हैं यह बताने का प्रयास मैंने किया है । बाद में वो समझ गए।

प्रश्न- 1950 में हमारा संविधान बन चुका था। उस संविधान में न्याय बंधुता समता समानता जैसे मूल्य थे। हमारी फ़िल्मों ने भी उन मूल्यों को आधार बनाकर फ़िल्में बनाई। क्या आज के दौर ऐसी फ़िल्में बन पा रही हैं? कुछेक फ़िल्मों का ज़िक्र अगर आप कर सकें।

मुझे चैतन्य तम्हाने की फ़िल्म अभी याद आ रही है । चैतन्य ने इस फ़िल्म से संविधान और कोर्ट की प्रक्रिया को यथार्थवादी ढंग से दिखाने का प्रयास किया हैं। उसमें एक दलित गायक है। वह वोरोध के गीत गाता है। निर्देशक ने इस फ़िल्म में कोर्ट में कहाँ कहाँ लोचा है कमियाँ हैं उसके क्या समाधान हो सकते हैं वो बताने का सफल प्रयास किया है। मैं इसे कोर्ट कचहरी और न्याय प्रक्रिया पर केंद्रित भारत की सबसे अच्छी फ़िल्म मानता हूँ।

प्रश्न- अकाल, भुखमरी, दूध, खेती-किसानी, शिक्षा, व्यवसाय, मकान, स्वास्थ्य, शोषण और असमानता आदि जैसी समस्याओं से भारत उन दिनों जूझ रहा था। संविधान से चलने वाली सरकारों पर भी एक चुनौती उससे जूझने की थी, समाज को इन समस्याओं से निजात देने की थी। उस दौर के फ़िल्मकारों ने सरकार और समाज की इस चुनौती को कैसे परदे पर दिखाया?

वह बहुत पढ़े लिखे लेखकों और निर्देशकों का दौर था । उस दौर में कलाकार भी खूब पढ़े लिखे और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए होते थे । छोटे क़स्बों शहरों से मज़बूत जड़े लेकर वें फ़िल्म की कहानियाँ बुन और निर्देशन कर रहे थे। पैग़ाम जैसी फ़िल्म या फिर उस दौर के गीतों को अगर आप देखें तो पाएँगे कि उसमें सामाजिक सवाल तो थे। प्रेमचंद ने मज़दूर नाम की फ़िल्म लिखी थी। धीरे धीरे हमारा सिनेमा ऐसे हाथों में चला गया जो सामाजिक रूप से जागरूक नही थे । वें सिर्फ़ पैसा कमाना और नाम कमाना चाहते हैं । इधर के 20-30 वर्षों में हमारा सिनेमा बहुत खोखला हो गया है। फ़िल्म तो 500-800 करोड़ कमाने लगी हैं लेकिन उन्मे मूल्य शून्य हैं। सरकार से लादकर भी फ़िल्में उस दौर में लिखी और बनाई जाती थी। बखूबी सवाल उठा कर सरकारों को चेताया भी जाता था। सरकार जो काम करती थी उन्हें सकारात्मक ढंग से भी पेश करते थे। लेकिन आज स्वरूप बदल गया है।

प्रश्न- 60 के दशक के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार हमें दिखाई देने लगता है, लेकिन सिनेमा के परदे पर मनोरंजन एक एलिमेंट बनकर सामने आता है। फ़िल्मकारों ने इसे कैसे अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी के तहत देखा ? क्या कोई कमी आप महसूस करते हैं जिसके चलते सिनेमा की धारा बदल गयी।

60 के दशक में औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में कई रूप में बदलाव आए। किसान से मज़दूर बनने लगे लोग। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गौतम घोष, श्याम बेनेगल का सिनेमा आप देखें तो उसी दौर में सामन्तवाद, साहूकारी, और किसानों की अनेक समस्याओं पर बेहतरीन फ़िल्में बनाई थी। निशान्त में सामंतवादी ताक़तों के ख़िलाफ़ संदेश है। श्याम बेनेगल की एक फ़िल्म मम्मो संवैधानिक संकट की फ़िल्म है। कई बार संविधान में संशोधन के लिए रास्ता भी दिखाता है सिनेमा । मम्मो उसका बेहतर उदाहरण है ।

वेल डन अब्बा मेरी लिखी फ़िल्म है । उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा था । कुआँ सिर्फ़ काग़ज़ों में खुद जाता है । असल समाज में उसका अता पता नही । ऐसी तमाम खबरें आती हैं मीडिया में । रिपोर्ट्स में । मैंने उस फ़िल्म में सरकार के ख़िलाफ़ नही कहा कुछ बल्कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में कितने गहरे रूप में पनप चुका है और उससे कैसे बचा जाए इसको दर्शकों के बीच रखने की कोशिश की है ।

प्रश्न- आपने सिनेमा के कई दशक देखें हैं । नए दशक का नया ओटीटी प्लेटफार्म भी आपके लिए अब नया नहीं रहा। वहाँ कैसे मानवीय मूल्यों के साथ सिनेमा बन पाएगा?

मैंने ओटीटी के लिए फ़िल्म कटहल लिखी थी जिसे यशोवर्धन मिश्रा ने निर्देशित किया है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है । हमें एक ख़बर पढ़ी थी जिसमें आज़म खान जैसे नेता के घर से भैंस चोरी चली गयी थी । वैसी ही एक घटना मध्य प्रदेश में हुई जिसमें एक एमपी के घर से दो कटहल चोरी चले गए थे । हमने उसी को आधार पर सामाजिक सवालों को उठाती फ़िल्म लिखी । इसमें कटहल के बहाने कई सामाजिक सवाल हैं दर्शक उसे देखेंगे तो समझ पाएँगे । फ़िल्म में एक दलित इंस्पेक्टर है जो कटहल चोरी के केस को अपने दिमाग़ से सुलझाती है और एक उसके चलते एक लड़कियों की चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ करती है। उसमें भी आप देखिए की उस लेडी इंस्पेक्टर ने मामले को दूसरी ओर मोड़ दिया लेकिन उसके पीछे भी उसके मन में सामाजिक सवाल ही था। उसके लिए कटहल से ज़्यादा ज़रूरी लड़की को खोजना था। इसलिए कोर्ट रूम सीन में भी वो इस बात को स्वीकार करती है । मेरी यह फ़िल्म सॉफ़्ट तरीक़े से सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करती है। मेरे पात्र मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए आपको दिखते हैं । जो मूल्य हीन उन्हें फ़िल्म के यही पात्र जवाब भी देते हैं। फ़िल्म को लेकर एक जगह दिक़्क़त आई थी, बसोड समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारा ये अपमान है। हमें उन्हें समझाया और बताया की बसोड समुदाय की लड़की इसमें हीरोइन हैं । मुख्य किरदार है। यह अपमान नही सम्मान है। ओटीटी पर भी मूल्यों के साथ फ़िल्में बनाई जा सकती हैं । लोग बना भी रहे हैं।

प्रश्न- देश में सिनेमा, मीडिया और संविधान की शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे ?

मैं कहता हूँ इस देश के 80 फ़ीसदी लोगों को संविधान की मूल भावना का ज्ञान नही है। इसके चलते वो सीनम और मीडिया में जो देखते हैं उसका ग़लत इंटरप्रिटेशन करके आंदोलित हो जाते हैं। बसोड़ समुदाय के लोगों ने जो मेरी फ़िल्म को लेकर आंदोलन किया उसके पीछे सिनेमा अध्ययन, मीडिया अध्ययन की कमी ही मुख्य कारण है । उन्होंने सिनेमा को ठीक से समझा नही और राजनैतिक या सामाजिक दबाव में आकर फ़िल्म का विरोध करने लगे । मुझे लगता हैं बचपन से ही मीडिया सिनेमा के साथ साथ संविधान की शिक्षा देने की आवश्यकता की वकालत करता हूँ । संविधान में संशोधन अगर होना भी है तो वह दलितों शोसितों के पक्ष में हो, और इसे समाज खुद अपने विवेक से समझें भी। तब जाकर हम समतामूलक समाज का सपना पूरा कर पाएँगे। सेंसरबोर्ड को मैं देखता हूँ वो भी अजब ग़ज़ब के फ़ैसले देता रहता है । इस फ़िल्म में ये ग़लत है वो ग़लत है। फिर जब कोर्ट में लोग जाते हैं वहाँ से जीत कर आ जाते हैं । उसके पीछे भी यही कारण है संविधान और सिनेमा की मूलभूत जानकारी ना होना। इन दोनों के अलावा हमें मानवीय गुण से लैस तो होना ही पड़ेगा। सिनेमा में धार्मिक विभाजन जो हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ हैं वह बहुत ही ग़लत धारा में जा रहे हैं हम लोग। हिंदू ने बनाई है फ़िल्म तो प्रमोट करें मुस्लिम शोसल है तो उसे सिर्फ़ मुस्लिम देखने जायें ये खेमे बहुत ख़तरनाक हो चले हैं। मक़बूल फ़िदा हुसैन साहब इसी हेट्स का शिकार हुए। हमें यह समझना होगा कि भारत का शास्त्रीय संगीत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बड़े ग़ुलाम अली खा साहब, अलाउद्दीन खान साहब, जैसों ने हमारे संगीत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे स्थापत्य कला को आप देखिए इसमें भी मुस्लिमों की भागीदारी को आप नज़रंदाज नही कर सकते।

प्रश्न- फ़िल्म लिखते समय मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्यों को क्या एक लेखक ध्यान में रखता है ? नए फ़िल्मकारों के लिए इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे आप?

मैंने एक फ़िल्म समर लिखी थी। यह फ़िल्म भी सच्ची घटना पर आधारित थी। दलितों के साथ हुए शोषण की कहानी थी ये। उस कहानी में मैंने दलित समाज का पक्ष भी हमने शामिल किया था। वहीं दूसरे आरोपी पक्ष को भी शामिल करते हुए उसकी सोच को फ़िल्म में जगह दी थी। वर्ग संघर्ष पर एक अच्छी फ़िल्म मुझे ये लगती है।

फ़िल्म को राष्ट्रीय फ़िल्म अवार्ड और मुझे इसके लिए बेस्ट पटकथा लेखन का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। लेकिन मुझे ये समझ नही आया की वो फ़िल्म रिलीज नही हो पाई। उसके क्या कारण रहे मुझे आज तक नही पता। जिस फ़िल्म का प्रदर्शन राष्ट्रपति भवन में हो चुका हो, महामहिम के आर नारायण साहब ने सभी राजनैतिक दलों के लोगों को इस फ़िल्म को देखने के लिए बुलाया । लेकिन यह फ़िल्म परदे पर आम दर्शक के लिए नही पहुँच सकी । फ़िल्म आख़िरी दृश्य मुझे आपकी बात से याद आ गया । उस फ़िल्म की कहानी में एक सच्ची घटना घटी हैं लोग उसे शूट करने आए हैं।

फ़िल्म दलित कलाकार उस में दृश्य में कहते भी हैं क्या डायरेक्टर साहब क्या ये फ़िल्म हमको देखने को मिलेगी। निर्देशक बने रजित कपूर कहते हैं मिलनी तो चाहिए। लेकिन देखिए हश्र क्या हुआ। फ़िल्म जिसके लिए बनाई जाती है वहाँ तक नही पहुँच पाती । ह्वरू 2 का भी वही हाल हुआ। बच्चों के लिए बनी और बच्चे ही उसे नही देख पाए। नए फ़िल्मकारों के लिए यही कहूँगा आप अनावश्यक हिंसा गाली अश्लीलता का सहारा ना लें ।

आपनी स्वच्छ कहानी भी दर्शकों को उतनी ही पसंद आएगी। अपने समाज के प्रति ईमानदार और संविधान के प्रति समर्पण भाव से फ़िल्म का निर्माण करें। मेरे बेटे यशोवर्धन ने ऐसी ही एक कोशिश की हैं अपनी फ़िल्म कटहल में । अभी एक फ़िल्म जवान आई। पूर्णतः व्यावसायिक फ़िल्म थी लेकिन उसमें निर्देशक और लेखक ने 5 फ़ीसदी ही सही सामाजिक संदेश डाले तो। इसका मतलब है दर्शक तैयार हैं आपकी फ़िल्मों के लिए। आप अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन तो कीजिए। सेक्स और हिंसा सबसे सरल तरीक़ा हैं सिनीम बनाने का । इससे फ़िल्मकारों को बचना चाहिए । मैं भी इन दिनों एक फ़िल्म बेरोज़गारी पर लिख रहा हूँ। उसमें भी आपको ऐसे ही मूल्य दिखेंगे जो समाज से सीधे जुड़ाव रखते हैं।

जल गंगा सवंर्धन अभियान

अमित राव पवार

लेखक स्तंभकार हैं।

वर्षा के जल को सहेजें, आओ कल को सँवारें

जीवन में प्रकृति-पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया है,तथा बदले में प्रकृति हमसे थोड़ी-सी कुछ अपेक्षा रखती है। उसमें भी हम मनुष्य शायद खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए समय- समय पर इसका ध्यान रखा। इसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।अब कुछ आधुनिकता के चलते हम अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा प्रकृति को अनदेखा करते जा रहे हैं,जिसका परिणाम हम सबको समय-समय पर दिखाई पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग,जल का स्रोत निम्न स्तर पर जाना,गर्मी में अधिक तापमान इत्यादि कारण जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात जल बचाने की है। जन्म से ही मनुष्य अपने आप को बहुत चालाक, चतुर और समझदार समझता था, हर जगह मानो उसकी हुकूमत हो,किंतु प्रकृति इस मनुष्य से भी कई अधिक चतुर,चालाक और समझदार निकली जिसने दो महत्वपूर्ण काम वायु-जल अपने हाथों में ही रखें। और यह दोनों ही चीज मनुष्य कभी निर्माण (काल्पनिक हो सकती है) नहीं कर सकता,इन दोनों के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ रहकर ही कार्य करना पड़ेगा! अधिक पेड़ लगाने होंगे तथा वर्षा का पानी सहजना होगा जिससे जल के स्तर को बढ़ाया जा सके अन्यथा हालात अभी आरंभ ही हुए हैं, नहीं तो जल और वायु से होने वाले दुष्परिणाम,संकट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हाल ही में गर्मी ने अपना रुद्र तापमान रूप दिखाया जिससे हाहाकार मच गई, विचार करे पानी का पर्याप्त मात्रा में न मिल पाना इससे भी अधिक खतरनाक समस्या साबित हो सकती है। हम जल को सहज सकते हैं, इसको बनाया या निर्माण नहीं कर सकते,इसलिए वर्षाकाल में हम सब मिलकर प्रयास करें जल को संवारने की, इसे सहेजने की,भूमि के जल स्तर बढ़ाने की,और अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उसे सुरक्षित रखते हुए पौधे से पेड़ बनने तक रखरखाव की जिम्मेदारी ले। तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देखकर जा पाएंगे।अन्यथा आज जो हम वायु-जल उपयोग कर रहे हैं,यह तो हमें हमारे पूर्वजों के कारण मिला है। हमारा इस प्रकृति- पर्यावरण में अब तक कोई योगदान नहीं है, इसलिए आओ जल को बचाएं व पेड़ लगाए हमारी छतों से हर वर्ष लाखों- करोड़ों लीटर पानी बह जाता है, इस बहते पानी को हम सहज सकते हैं दो या तीन तरह से,छत पर आने वाले वर्षा जल को एक फिल्टर के माध्यम से सीधे नलकूप में उतारकर,रूफ हावेस्टिंग सिस्टम,सोकपिट बनाकर,अन्य किसी विधि द्वारा। आसानी पूर्वक जैसा हम कर सकते,जिससे जल बहकर न जाते हुए भूमि के अंदर जाए जिससे जल के स्तर को बढ़ाया जा सके।

दुनिया के हर जीव को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अध्ययन के मुताबिक मनुष्य पांच दिन बिना कुछ खाए रह सकता है। किंतु बिना पानी के एक दिन भी नहीं। आज भी अनेक देश और राज्य ऐसे हैं जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं जल की खपत लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती जा रही है,वहीं इसकी उपलब्धता में कमी दिखाई पड़ती है।पानी की कमी को पूरा करने के लिए सकारात्मक तथा प्रभावी कदम अपनाने ही होंगे। यदि हम निष्कर्ष निकाले तो बिना जल के जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। पेड़-पौधों को भी जल की उतनी ही आवश्यकता होती जितनी मनुष्य को होती है।जल के बिना कोई भी पेड़-पौधें विकसित नहीं हो सकते और मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़-पौधों का जीवित रहना आवश्यक है।अतः वर्षा के जल को सहजे,आओ कल को सँवारे।

शासन-प्रशासन सरकारें सब अपना काम कर रहे है,लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है,कि वह जल का अपव्यय न करे इसे सहज कर रहे। कोई भी सरकार आ जाए कितने ही कानून बन जाए पर हम जल को उत्पन्न नही कर सकते है। वर्षा और पेड़ो से ही भूमि के जल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आज देश के कितने ही नगरों में जल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, विकास के नाम पर सीमेंट का झाल छा रहा है दूर-दूर तक पेड़-पौधों का नाम तक नही,जल होगा तो सप्लाय होगा या जल की व्यवस्था होगी तभी शासन-प्रशासन सरकारें कुछ कर पाएगी,अन्यथा हम कितने ही आंदोलन करे कितने ही ज्ञापन दे कोई फर्क नही पड़ने वाला हम भूमि से जल निकाल ही रहे है उसे दे कुछ नही रहे।नदिया सिकुड़ रही,तालाब सुख रहें, बावड़ियां अब पोस्टरों पर दिखाई देती है। इसलिए अभी समय रहते हम सबको संभलना होना अन्यथा आने वाले समय मे जल के लिए भीषण लड़ाइयां और युद्ध तय है।

दृष्टिकोण

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

मोदी की अग्नि परीक्षा- नई चुनौतियां व गठबंधन सरकार

सख्त शंकाओं एवम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए अंततः तीसरी बार मोदी ने प्रधान मंत्री पद की शपथ लेकर भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय और जोड़ दिया । वे देश के दूसरे ऐसे प्रधान मंत्री बन गए जो लगातार तीसरी बार इस पर आसीन हुए । बावजूद इसके इस बार मोदी के सामने पहले से अधिक चुनौतियां है। इनमें से सबसे प्रमुख गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करने उनका यह पहला अनुभव है। इससे भी महत्वपूर्ण यह कि गठबंधन में संख्या की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण दल जेडीयू एवम टीडीपी अपने हितों को ध्यान में रखते अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, किसी कारण से उनकी मांगों को स्वीकार ना कर पाने की स्थिति में वे गठबंधन से बाहर जा सकते है , जो उनका इतिहास रहा है । जातिगत जनगणना, यूसीसी, अग्निवीर पर जेडीयू एवं मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी की नीति का बीजेपी से वैचारिक मतभेद सर्व विदित है । दोनो दलों द्वारा अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पहले से की जा रही है । कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका वे अपने तीसरे कार्यकाल में निराकरण करने का मन बना चुके थे ,पूरा कर पाएंगे इस पर संशय है । किसी भी गठबंधन के स्थायित्व के लिए विवादित मुद्दों का सर्व सामान्य समाधान सबसे प्रमुख कारक होता है, अतः मोदी को बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की चुनौती सामने है ।

इनके अतिरिक्त मोदी के लिए अपने बलबूते बीजेपी के बहुमत में ना आने से ज्यादा चिंता यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल में बुरी हार और बिहार, कर्नाटका एवम हरियाणा में सीटों की संख्या कम होना है। इसमें से भी यूपी एवम महाराष्ट्र की हार ऐसी है, जहां मोदी, अमित शाह के सामाजिक समीकरण के सामने अखिलेश राहुल के पीडीए के फॉर्मूले, संविधान में बदलाव कर आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे के अतरिक्त इंडी गठबंधन का पूरी ताकत के साथ एकजुट होना रहा । राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा, बंगाल जैसे राज्यों में गलत उम्मीदवार, कमजोर संगठन, गुटबाजी, अग्नि वीर, किसान आंदोलन एवम स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ने अपना असर दिखाया । किसानों की समस्या, बेरोजगारी एवम महंगाई जैसे मुद्दे 2014 से आजतक बने हुए है, लेकिन किसी भी गठबंधन की हार जीत में मुख्य या राष्ट्रव्यापी मुद्दे नही बन पाए । अभी तक बीजेपी की जीत में लाभार्थी वर्ग एवम महिलाओं का पूर्ण समर्थन सबसे बड़ा कारक रहा है । लेकिन आरक्षण की समाप्ति का डर एवम लाभार्थी वर्ग को मुफ्त राशन योजना को अपना हक समझने का विश्वास दिलाकर विपक्ष ने इस वोट बैंक को अपनी और खींच लिया। मध्यम वर्ग की महिलाओं में अपनी रसोई का खाद्य पदार्थों की अनाप शनाप बढ़ोतरी के कारण बजट बिगड़ने से बहुत असंतोष नजर आया। यूपी में मुस्लिम मतदाता अभी तक सपा एवम बसपा में विभाजित होता रहा , इस बार उसने एकजुट होकर सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। इसके विपरीत बीजेपी अपने वोट बैंक को एक जुट नही रख पाई। इस वोट बैंक का फिर से विश्वास अर्जित करना मोदी के लिए अगली चुनौती है।

महंगी होती शिक्षा एवम स्वास्थ्य सेवाओं का निम्न मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक बोझ, विशेष रूप से जो आरक्षण से वंचित है, बहुत कठिन हो गया है। रेल्वे सेवाओं में गुणात्मक सुधार हुआ है, मगर मध्यम वर्ग के लिए अनारक्षित एवम स्लीपर कोच को कमकर वातानुकूलित कोच की बढ़ोतरी से सफर महंगा हो गया है। इस कारण यूपी, बिहार से लाखों लोग जो रोजगार के लिए दूर दराज के राज्यो में मजदूरी या अन्य सेवाओं में है, प्रभावित हो रहे है। वे सीनियर सिटीजन जिसे किसी भी दल ने वोट बैंक नही माना, कोरोना के बाद से टिकिट में रियायत बंद होने से दुखी होने के अतरिक्त कर भी क्या सकते है। केंद्र की एक योजना विधवा एवम अविवाहित महिलाओं को पारिवारिक पेंशन के हक को उन राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में है, लागू करने से उनके आत्म विश्वास, भविष्य की चिंताओं, महंगाई एवम बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाने में मददगार होंगी। कहने के लिए यह सब बहुत छोटे छोटे कारण है, मगर अन्य मुद्दों के साथ मिलकर व्यक्ति की सोच को प्रभावित तो करते है।

इनके अतिरिक्त सीमा पर तनाव, खालिस्तान जैसे अलगाववादी तत्वों को विदेशी सहायता, आतंकवाद, पड़ोसी राज्यों से घुसपैठ जैसी समस्याओं से किस तरह निपटा जाए यह चुनौती हमेशा बनी रहती है ।

2019 के चुनाव में मोदी के अपने दम पर अप्रत्याशित बहुमत ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी साख और धाक को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, किसी भी संकट के समय उनकी राय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस बार सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी को अन्य राष्ट्र किस तरह से देखते है , विदेश नीति एवं उनकी अपनी साख पर इसका क्या असर होंगा यह भी मोदी के लिए एक चिंता एवम चुनौती का विषय है ।

देश की संसद में इस बार मजबूत विपक्ष चुन कर आया है , मोदी के लिए उसके प्रहार को किस तरह निष्फल किया जाय यह बहुत बड़ी चुनौती है। उम्मीद है विपक्ष हो हल्ला एवम वाक आउट की रणनीति छोड़कर वाक युद्ध से मोदी के लिए चुनौती खड़ी करेगा ।

इन समस्त चुनौतियों एवम आशंकाओं के बावजूद मोदी के खाते में लागतार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने, मप्र, गुजरात, देहली, छग, ओडिसा, हिमाचल प्रदेश, आसाम जैसे राज्यों में पार्टी की अप्रत्याशित सफलता, दक्षिण में पार्टी का विस्तार, धारा 370 की समाप्ति, राममंदिर निर्माण, विश्व की पांचवी बढ़ी अर्थव्यवस्था, वंचित वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं, देश के इंफ्रा स्ट्रक्चर में विकास की दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति जैसी कुछ ऐसी उपलब्धियां है , जो यह कहती है कि मोदी राजनीतिक रूप से कुछ कमजोर जरूर दिखाई दे रहे है लेकिन उनकी ताकत में बहुत बढी कमी आई हो, कहना अनुचित होंगा । यह जरूर है की सामाजिक न्याय की उनकी सोच, सत्ता का केंद्रीयकरण, विपक्षी पार्टियों में विभाजन, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, अपने दल के पुराने एवम वरिष्ट कार्यकर्ताओं की अनदेखी, अन्य दलों से आए हुए नेताओं को हर स्तर पर प्राथमिकता देने की नीति का मतदाता ने कड़ा विरोध जताते हुए एक तरह से चेतावनी दी है । उम्मीद है मोदी इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेते हुए, गठबंधन के साथी दलों के बीच सामंजस्य एवम संतुलन बनाते हुए राष्ट्र हित के कदम उठाते रहेंगे। यह समय ही तय करेगा कि मोदी इन चुनौतियों की अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए कितने सफल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव के आगमन की तैयारियों की कलेक्टर ने की पूर्व समीक्षा

जिला स्रोत समन्वयक जितेंद्र भनारिया ने संभाला बैतूल डीपीसी का पदभार

- शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ देकर किया गर्मजोशी से स्वागत

बैतूल। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करते हुए, जिला स्रोत समन्वयक जितेंद्र भनारिया ने बुधवार 12 जून को डीपीसी का पदभार संभाला। इस अवसर पर शिक्षक और कर्मचारियों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री भनारिया ने अपने संबोधन में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्वागत समारोह में राजकुमार राठौर, रवि सरनेकर, राजेंद्र कटारे, धनराज पाटील, संतोष मरस्कोले, गोकुल झरबडे, रवि अतुलकर, गुणवंत खातरकर, और छिंदवाड़ा से आए अरविंद भट्ट शामिल थे। सभी ने पुष्पगुच्छ देकर डीपीसी का स्वागत किया और उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। डीपीसी ने अपने स्वागत में सभी उपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह बैतूल जिले की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके।

बाइक को लेकर विवाद, बेटे ने किया पिता पर हमला

- पिता की हालत गम्भीर, जिला अस्पताल में भर्ती

बैतूल। एक शराबी पुत्र ने पहले अपने पिता से विवाद किया और उसके बाद पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल पिता को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छन्बू उड़के उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम चिरापाटला थाना चिचोली का मंगलवार रात अपने बेटे महेश उइके से विवाद हो गया और विवाद में बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता के साथ विवाद करते हुए मारपीट कर दी और अपने पिता पर पत्थर से हमला कर दिया, इस मारपीट में बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। घायल बुजुर्ग छन्नू ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसका बेटा महेश एक महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल लेकर कहीं चला गया था, जो कल घर वापस आया। जहां मैंने उसे कहा कि तू एक महीने से कहा था और किस से पूछकर मेरा वाहन लेकर गया था। युवक शराब के नशे में था, इसके बाद युवक ने घर में ही विवाद शुरू कर दिया और विवाद करते- करते अपने ही पिता के साथ मारपीट की और पिता पर पत्थर से हमला कर दिया। जिसमें बुजुर्ग को कान और हाथ में गंभीर चोटें आई है। वही बुजुर्ग ने बताया है कि उसका बेटा हमेशा विवाद करते रहता है, वहीं जमीन को लेकर भी आए दिन घर में लड़ाई करता है। जैसे ही मारपीट की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजन बुजुर्ग को पहले चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को 108 एंबुलेंस की सहायता से देर रात जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वही इस पूरी घटना की शिकायत परिजनों ने चिचोली थाने में भी की है। फिलहाल घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है।

शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश अब 20 जून तक

बैतूल। शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में संचालित 10 ट्रेडो में प्रवेश की प्रक्रिया हेतु पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई है। इच्छुक आवेदक अब आगामी 20 जून तक की समयावधि में पोर्टल पद पर पंजीयन एवं च्वाइस फीलिंग करा सकेंगे। प्रथम चयन सूची 28 जून को जारी की जाएगी एवं 01 जुलाई 2024 से प्रवेश दिया जाएगा। संस्था प्राचार्य रेवाशंकर पंडाग्रे ने बताया कि संस्था में संचालित इलेक्ट्रीशियन (एनसीवीटी), इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक (एनसीवीटी), और इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन एण्ड सिस्टम मेंटेनेंस (एनसीवीटी), मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर (एससीवीटी) दो वर्षीय पाठ्यक्रम है। स्वींइग टेक्नोलॉजी (एनसीवीटी) ऑफिस असिस्टेन्ट कम्प्यूटर ऑपरेटर (एससीवीटी) फ्लोरीकल्चर एण्ड लेण्ड स्केपिंग (एनसीवीटी), स्टेनो अंग्रेजी (एनसीवीटी), स्टेनो हिन्दी (एनसीवीटी) एवं कोपा (एनसीवीटी) एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। इन व्यवसायों में से स्वींइग टेक्नोलॉजी (एनसीवीटी) हेतु योग्यता आठवीं उत्तीर्ण है। शेष सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संस्था प्राचार्य श्री पंडाग्रे ने बताया कि इन सभी ट्रेडो में कुल 324 सीटे उपलब्ध है। अंग्रेजी माध्यम या अंग्रेजी में अच्छी पकड़ रखने वाली छात्राओं के लिये स्टेनो अंग्रेजी ट्रेड एक रोजगार परक अवसर है। यह संस्था मध्यप्रदेश शासन की एकलव्य योजना अंतर्गत संचालित है, जिसमें सभी वर्ग की छात्राओं को प्रवेश की पात्रता है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित है एवं इस वर्ग की छात्राओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं भोजन सहित छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।

कार्यक्रम की गरिमा और भव्यता का रखें ध्यान : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के 14 जून शुक्रवार को मुलताई आगमन की पूर्व तैयारियों की कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वर्चुअली एवं समक्ष में उपस्थित अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.यादव के हेलीपैड स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, कारकेट, पर्याप्त बेरिकेडिंग, अतिथि कक्ष एवं चिकित्सा दल के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत जैन और एडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव विश्व पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लोगों को अभियान से जोडने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से जनसमुदाय से आव्हान करेंगे। इस यात्रा में महिलाएं एवं कन्या कलश सिर पर रखकर इस यात्रा की अगुवाई करेंगी। यात्रा के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ.यादव मां ताप्ती की पूजा-अर्चना करेंगे।

इसके पश्चात श्रमदान कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव सीएम राईज स्कूल के खेल मैदान पर आमसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अनेक योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नगर पालिका, एसडीएम, महिला बाल विकास, माइनिंग, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ताओं एवं ट्राइबल एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यक्रम की भव्यता और गरिमा के अनुरूप व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हितग्राहियों के भोजन, पानी, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं सभी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री आगमन की तैयारी को लेकर नपा में हुई बैठक

विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग

- रोड शो को देखते हुए नगर के मुख्य मार्ग से हटाया अतिक्रमण

बैतूल/ मुलताई। 14 जून को प्रस्तावित मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुलताई नगर आगमन की तैयारियां अंतिम चरण में है । बुधवार को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका सभाकक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री के आगमन की लेकर रूपरेखा बनाई गई ।इस बैठक में मुलताई ,अमला, शाहपुर के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और जिले के अनेक नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया । बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नाका नंबर एक से ताप्ती उद्गम तक रोड शो करेंगे। इसके उपरांत ताप्ती उद्गम स्थल पहुंच कर ताप्ती मंदिर में पूजा के उपरांत ताप्ती घाट पर जलाभिषेक एवं श्रमदान में भाग लेंगे।

एसडीएम नहीं लिया सभा स्थल का जायजा- उत्कर्ष विद्यालय मिनी स्टेडियम पर मुख्यमंत्री की आम सभा के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। बीती रात पानी आने से जमीन गीली होने से कार्यक्रम को लेकर चिंताएं होने लगी थी। आज एसडीएम तृप्ति पटैरिया, लोक निर्माण एसडीओ राजेश राय सहित आला अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और बनाए जा रहे स्टेज को लेकर सुझाव दिए।

बस स्टैंड से नाका नंबर एक तक मुख्य मार्ग का हटा अतिक्रमण- मुख्यमंत्री के नगर आगमन को देखते हुए नपा राजस्व निरीक्षक जीआर देशमुख के नेतृत्व में नपा के अमले ने नाका नंबर एक, बाबा साहब अंबेडकर चौक ,आंग्ल स्कूल, ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के सामने, जय स्तंभ, चौक थाना परिसर के समक्ष एवं नाका नंबर एक का अतिक्रमण हटाकर मुख्य मार्ग को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। 17 दुकानों के सामने लगी दुकानों को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है।

क्या ताप्ती लोक की घोषणा लेने जा रही है आकार

- ताप्ती प्रवाह क्षेत्र के विकास की संभावनाएं बड़ी

बैतूल/ मुलताई। पवित्र नगरी मुलताई से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन प्रदेशों को सीचकर सुख, समृद्धि का वरदान देने वाली ताप्ती नदी, जिसे सृष्टि की प्रथम नदी आदि गंगा भी कहा जाता है, का अपना धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रहा है। किंतु यह धार्मिक पौराणिक महत्व आस्था से जुड़े लोगों तक ही सीमित रहा। राजनीति एवं प्रशासनिक रूप से ताप्ती उद्गम स्थल को संवारने और संजोने के प्रयास कभी नहीं हुए और ना ही ताप्ती प्रवाह क्षेत्र के विकास के प्रयास हुए। एक वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताप्ती कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी किंतु अब तक घोषणा के अलावा कुछ नहीं हो सका है।

किंतु हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नमामि गंगा जल संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है जिसके तहत 14 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुलताई आगमन हो रहा है तो यह माना जा रहा है कि ताप्ती लोक की आधारशिला रखी जा सकती है। हाल ही में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से नमामि गंगा जल संवर्धन अभियान के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने नर्मदा बेतवा के साथ ही ताप्ती का भी नाम लिया जिससे यह

संभावना बढ़ जाती है कि मुलताई के लिए मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है जिससे ताप्ती विकास की संभावना बनती है।

जिले में ताप्ती के ढाई सौ किमी सफर को बनाया जा सकता है वरदान- ताप्ती अपने उद्गम स्थल मुलताई से निकलकर 724 किलोमीटर का सफर तय कर खंभात की खाड़ी अरब सागर में समा आती है। ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा के बाद देश की दूसरी लंबी नदी है। जिसके तट पर अनेक तीर्थ स्थित है। ताप्ती की विशेषता यह है कि यह बैतूल जिले में अपना ढाई सौ किलोमीटर का सफर तय करती है । इसके जल को संग्रहित और संवर्धन कर न सिर्फ जिले के लिए वरदान बनाया जा सकता है बल्कि ताप्ती के तट पर स्थित ग्राम साडिया, डोहलन, पंचधार, श्रवण तीर्थ, छींदखेड़ा को ताप्ती पथ से जोड़कर सुंदर धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है और यह सभी ग्रामों में कभी भव्य मंदिर होने के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं अनेक स्थानों को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इन प्राचीन मंदिरों के अवशेषों को संग्रहित क्षेत्र घोषित किया है।

ताप्ती लोक पहली प्राथमिकता, मुख्यमंत्री से करेंगे आग्रह भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर मुख्यमंत्री के नगर आगमन को लेकर उत्साहित है। उन्होंने चर्चा में बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता पूर्व मुख्यमंत्री की मुलताई लोक की घोषणा का क्रियान्वयन और शुभारंभ करना है । इसके लिए सभी परिषद एवं पार्षद गण मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ताप्ती लोक को लेकर नगर को सौगातें मिल सकती है। ताप्ती लोक के तहत कारमाटीयां बांध निर्माण होगा, बांध से सरोवर तक नहर बनाई जाएगी। जिसका सौंदर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अनेक स्थानों पर बैराज बनाए जाएंगे, साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय और प्रतीक्षालय में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो रहेगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान

विधायक डॉ. पंडाग्रे ने जल मानस यात्रा व गहरीकरण कार्य का किया शुभारंभ

बैतूल। आमला-सारणी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की प्रेरणा से जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन प्रदान करने के ध्येय के साथ प्रदेश में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत अम्बाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख जीवनदायिनी बेल नदी के उदगम स्थल पर मानस यात्रा का शुभारंभ एवं वृक्षारोपण कर जल सम्मेलन को सम्बोधित किया।

जल संरक्षण का किया आव्हान- जल की प्रत्येक बूंद का महत्व बताते उन्होंने कहा कि हम सभी जन सहयोग के माध्यम से क्षेत्र की सभी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करे। उन्होंने बेल नदी के उदगम स्थल पर देवी स्वरूपा कन्याओं एवं कलश पूजन कर जनसहयोग से गहरीकरण एवं घाट की साफ-सफाई का कार्य किया एवं उसके बाद् पौधरोपण भी किया । इस अवसर पर जल सम्मेलन में जनपद पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गढेकर एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकिशोर देशमुख, हरी यादव, किसन सिंह रघुवंशी, दिलीप माथनकर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं अधिकारी. कर्मचारीगण उपस्थित थे।

जल संरक्षण हेतु व्यापक स्तर पर 'जलता बैतूल अभियान' चला चुके है विधायक डॉ. पंडाग्रे- जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे सतत प्रयासशील रहे है। अपने पिछले कार्यकाल में भी भुमिगत जल आवर्धन के लिए आमला सारणी विधानसभा में जन सहयोग के माध्यम से व्यापक स्तर पर जलता बैतूल अभियान चलाकर जल संरक्षण की मुहिम को तेज किया था।

हाईवे पर फिर हादसा, एक की मौत, महिला समेत दो गंभीर घायल

बैतूल। भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को फिर एक हादसा हो गया। इसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। जबकि एक महिला समेत 2 लोग घायल हैं। इससे पूर्व सोमवार रात्रि में एक बाइक सवार वैन से टकरा गया था।

इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम एनस निवासी हरिराम मालवीय (57), पत्नी उमाबाई (50) के साथ ग्राम बानूर में आयोजित टीका कार्यक्रम में गए थे। मंगलवार शाम को कार्यक्रम में शामिल होकर वे बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान शाम 5 बजे हाईवे पर उभरिया और एनस जोड़ के बीच रांग साइड से बाइक लेकर आ रहे सुखलाल उईके (35) निवासी ग्राम उभारिया की बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में हरिराम, उमाबाई और सुखलाल घायल हो गए।

एंबुलेंस से लाया अस्पताल: सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के पायलट अजाब साहू और ईएमटी मनोज साबले ने तीनों घायलों को उपचार के लिए मुलताई अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने हरिराम मालवीय को मृत घोषित कर दिया। सुखलाल और उमा बाई को हाथ में चोट आने पर बैतूल रेफर किया गया है।

मारुति वैन से टकराया बाइक सवार, गंभीर रूप से हुआ घायल: मुलताई नगर के समीप नेशनल हाईवे 47 पर हवेली रेस्टोरेंट के पास बीती रात एक बाइक सवार युवक मारुति वैन से जा टकराया। जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डायल हंड्रेड के माध्यम से मुलताई नगर के सरकारी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। जहां पर उसका उपचार किया गया।

मोबाइल के कारण हादसा: प्राप्त जानकारी अनुसार पांढुरना ग्राम सिल्लेवानी निवासी 18 वर्षीय दुर्गेश पुत्र देवलू तुमड़ाम बीती रात बालाजीपुरम जा रहा था। इसी बीच हवेली रेस्टोरेंट के पास चलती बाइक पर उसने मोबाइल निकाला। तभी अचानक सामने चल रही मारुति ओमनी से उसकी भिड़ंत हो गई। जिससे वह गिरकर घायल हो गया। उसकी बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

पुलिस ने करवाया भर्ती

दुर्गेश के घायल होने के बाद सूचना डायल हंड्रेड को दी गई। जिसके बाद डायल हंड्रेड मौके पर पहुंची और घायल को मुलताई नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर उसका प्राथमिक उपचार किया गया।

पर्याप्त सुरक्षा न होने एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत 47 विस्फोटक लाइसेंस कलेक्टर ने किए निरस्त

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पर्याप्त सुरक्षा न होने एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत जिले में 47 विस्फोटक लाइसेंस धारी के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा समय-समय पर दिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर द्वारा जिले में अवस्थित विस्फोटक अनुज्ञप्तियों के संबंध में तहसीलदार के माध्यम से जांच परीक्षण कराया गया था।

कंप्रेसर युक्त ट्रैक्टर के 18 लाइसेंस

एडीएम श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कंप्रेसर युक्त ट्रैक्टर के लिए फार्म एलई-4 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जारी 18 लाइसेंस निरस्त किए गए तथा आतिशबाजी एवं पटाखा भंडार हेतु एलई-5 में जारी 29 लाइसेंस निरस्त किए गए। एडीएम श्री श्रीवास्तव ने बताया कि निरस्तीकरण की कार्रवाई अनुज्ञप्तियां एवं अनुज्ञप्त स्थलों पर अपर्याप्त सुरक्षा एवं अनियमितता पाए जाने पर की गई है। कलेक्टर द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्तियों की सतत जांच एवं निरीक्षण के लिए विस्फोटक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

प्रशिक्षण शिविर की बैठक संपन्न

बैतूल। दि बुद्धिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया की बैठक बौद्ध विहार कालापाठा में संपन्न हुई। मीराताई ताई अम्बेडकर बैतूल संगठन के अध्यक्ष शंकरराव शेषकर ने बताया कि बैठक में संगठन द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो 16 जून को डॉ.अम्बेडकर भवन कारगिल चौक में आयोजित किया जाएगा उसकी अंतिम रूपरेखा बनाई गई और सभी को दायित्व सौंपे गए।

बाढ़ की संभावना लेकर संभागायुक्त चिंतित हुए जिन्होंने सभी कलेक्टरों को बाढ़ से बचाव की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा..

बाढ़ की दृष्टि से जिला संवेदनशील : कलेक्टर

नर्मदापुरम। संभागायुक्त पवन शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ नियंत्रण की बैठक ली। उन्होंने नर्मदापुरम सहित भोपाल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे जल भराव क्षेत्र को चिन्हित करें। जहां जल भराव वाले क्षेत्र से जल की निकासी बाधित होती है। ऐसी जगह अगर अतिक्रमण है तो उसे तत्काल हटाए। संभावित बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां अभी से सुनिश्चित कर लें। उक्त निर्देश नर्मदापुरम / भोपाल संभाग आयुक्त डॉ पवन शर्मा ने बाढ़ नियंत्रण बैठक में दिए हैं।

डॉ शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदा पुरम एवं भोपाल संभाग के जिलों के कलेक्टर से बाढ़ से बचाव की तैयारी के संबंध में जानकारी ली, बैठक में नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि बाढ़ की दृष्टि से नर्मदापुरम जिला संवेदनशील है। मुख्य भराव क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, विशेष तौर पर बंगाली कॉलोनी एवं ग्वालटोली के कुछ हिस्सों में पानी का भराव हो जाता है। 70 से 80 जर्जर घर एवं भवन पूरे जिले में चिन्हित किए गए हैं और उन सब को नोटिस जारी किए गए हैं। जिले में डीप ड्राइविंग, लाइव जैकेट, स्कूबा ड्राइविंग, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। नर्मदापुरम के एनआईसी कक्ष में मौजूद आईजी नर्मदापुरम इरशाद वली ने बताया कि होमगार्ड पुलिस एवं

राजस्व की संयुक्त टीम तीन दिन के अंदर क्षेत्र का सर्वे कर लेगी। जहां बैक वॉटर से नदी एवं नालों में पानी का भराव होता है उसे विशेष तौर पर चेक किया जाएगा। बैक वॉटर क्षेत्र में अतिक्रमण को भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। जिन पुल एवं पुलिया में मोटर साइकिल बह जाती है, वहां पर विशेष तौर से मुनादी कराकर पहले से ही लोगों को सचेत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिव किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई संदेशों का आदान-प्रदान हो जाता है। नर्मदापुरम के एनआईसी कक्ष में उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौर, जल संसाधन विभाग के ईई वीके जैन, जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री जैन सहित संबंधित अधिकारी गण मौजूद थे।

संभागायुक्त सहित जिला कलेक्टर और आईजी की बाढ़ को लेकर जिले सहित मुख्यालय की चिंता जायज है। मुख्यालय पर जल भराव बंगाली कालौनी सहित ग्वालटोली क्षेत्र को कलेक्टर ने चिंहित किया और कलेक्टर ने जिले को बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील बताया आईजी साहब ने जलभराव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जायेगा आश्वासन देकर आने वाली बाढ़ से बचाव और सारे इन्तजामात से निश्चिंत ही संभागायुक्त की बाढ़ को लेकर चिंता वाला कोरम पूरा किया लेकिन कोई जिम्मेदार यह गारंटी नहीं दे सकता कि नर्मदा में बाढ़ की स्थिति में नगर में गिरने वाले आसमानी पानी के भराव से नगर को बचाया नहीं जा सकेगा..! बंगाली कालोनी (भोपाल तिराहा) डूब क्षेत्र है नियम विरुद्ध गार्डन बनाने से आसमानी पानी की निकासी बाधित होने से नर्मदा बिहार कालोनी, नारायण नगर, गीता मैरिज पैलेस कालोनी और उसके नीचे की और कई रहायसी कालोनियां इससे प्रभावित होती है और अब तो इसके बाजू में ही ढाई एकड़ का रकबा चोरी की मिट्टी से भरा गया है।

तत्कालीन कलेक्टर ने उस पर स्टे लगाया जो यथावत है, लेकिन खनिज विभाग ने इस मामले में अबतक कार्रवाई नहीं की न मिट्टी हटवाई, न जुर्माना किया..? जिसने दूसरी पुलिया से निकासी प्रभावित कर दी। ऐसे ही डोंगर बाड़ा डूब क्षेत्र में हजारों डम्फर अवैध मिट्टी का भंडारण नगर के पानी की निकासी तो प्रभावित करता है और करेगा। ऐसे ही इतवारा बाजार क्षेत्र में नगरपालिका ट्रको से हर साल नाले की सफाई कर मलबा निकाल रही जबकि नाले के उपर पक्की दुकाने निर्मित है, नीचे बाजार हलवाई चौक क्षेत्र का भी यही हाल है यहां चेम्बर बना कर बरसाती पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है जबकि नाले के उपर दुकान निर्मित है। यहां सड़क पर बरसाती पानी तीन फुट के करीब उपर बहता है।

एक माह चलने वाले समर कैंप में खिलाड़ियों को तराशा

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए

सुबह सवेरे सोहागपुर।
जिला कलेक्टर सोनिया मीना, पुलिस अधीक्षक गुरूकरण सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत,जिला खेल अधिकारी कुमारी उमा पटैल के निर्देशानुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम नगर अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री यशवंत पटेल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर बी चौधरी,सी. एम राइस प्राचार्य रामकिशोर दुबे, ब्लॉक खेल अधिकारी हेमराज सिंह नागा ,अकादमी अध्यक्ष श्री हमीर सिंह चंदेल , खेल एवं युवा कल्याण विभाग समन्वयक चंदा मिश्रा , एजीपी शंकर लाल मालवीय रंजन यादव आदि के आतिथ्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम संचालक मनोज गोलानी, एकम सिंह राजपूत, सौरभ तिवारी दादूराम कुशवाहा, जयंत रघुवंशी आदि ने किया।ब्लॉक खेल समन्वयक चंदा मिश्रा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर में एक महीने तक हांकी, वॉलीबॉल फुटबॉल एवं बैडमिंटन खेल की बारीकियां खिलाड़ियों को सिखाकर नौनिहालों को तराशा गया। इस समय कैंप में कई नवीन प्रतिभाओं का उदय हुआ है। जो आगामी समय अपनी प्रतिभा का प्रर्दशन करेंगे। इसके अलावा 5 जून को खिलाड़ियों ने पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश दिया। इसी तारतम्य में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत खिलाड़ियों ने जल संरक्षण पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया ।समर कैंप में खेल प्रशिक्षक अश्वनी सरोज,आशू राय,लतीफ शाह, दर्शन डोंगरे ,हेमलता राय आदि ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने समर कैंप में भागीदारी निभाने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किए। इसी तारतम्य में वॉलीबॉल एवं हॉकी मैत्री प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

नगर पंचायत परिषद के साथ जन अभियान परिषद ने संयुक्त जल गंगा संवर्धन अभियान में की भागीदारी

हीरालाल गोलानी सोहागपुर ।
नगर पंचायत परिषद के साथ जन अभियान परिषद ने संयुक्त जल गंगा संवर्धन अभियान में भागीदारी निभाई। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत, जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल, उपयंत्री आर.जी. चौबे,प्रदीप दुबे, एच.एल. परते,नरेंद्र धुर्वे,सूर्यनारायण पठारिया,राधेश्याम रघुवंशी, हरगोविंद व्यास,नीरज मलैया, अनिल रघुवंशी,राजेश रघुवंशी, रणधीर रघुवंशी,राजेश मौर्य विनोद कुमार,राज कुमार घारू जन अभियान परिषद् के विकास खंड समन्वयक किशोर कड़ोले ,नवांकुर मेंटर गजेंद्र ठाकुर, श्याम सिंह मीना, सचिव विश्व, मेहरवान सिंह, संदेश मिश्रा, सफी खान,रानु मालवीय, वकील शिव कुमार पटेल आदि ने जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए। 5 जून से प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम अंतर्गत अभियान के सातवें दिन नगर पंचायत परिषद एवं जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पलकमती नदी के रामगंज वार्ड पुल के पास स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों , कर्मचारियों एवं समिति के सदस्यों ने कचरा उठाकर श्रमदान किया। वहीं जेसीबी मशीन के द्वारा नदी में एकत्रित कचरे एवं घास को साफ किया गया।

गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं करने पर उच्च न्यायालय में पक्षकार बनाएं जायेंगे थाना प्रभारी

नर्मदापुरम। नगरपालिका द्वारा मशीन से नाले की सफाई कर कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया जाने से नारायण नगर के समीप मोटरसाइकिल सवार भाई बहन की बस की चपेट में आने से हुई मौत को लेकर जिला आम आदमी पार्टी आरटीआई विंग जिलाध्यक्ष सीताशरण पाण्डेय द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमश्वरी पटले और नगरपालिका स्वच्छता निरीक्षक कमलेश तिवारी पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण न्यायादिष्ट किए जाने का मामला अब गंभीर हो गया। कलेक्टर को मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए सीधे सीधे लिखा कि दुर्धटना का मूल कारण प्राईवेट बस चालक द्वारा अनियंत्रित गति से बस चलाना है।बस चालक द्वारा पल्सर गाड़ी के चालक के हैंडिल पर टक्कर मारी गई जिससे उसकी बाईक अनियंत्रित हुई एवं वाहन में बैठी युवती की मृत्यु बस के नीचे आने से हुई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि नगर पालिका परिषद द्वारा वर्षा पूर्व नाले नालियों की सफाई कार्य अनिवार्य कर्तव्यों के अंतर्गत शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कराती है। उक्त घटना वास्तव में एक दुर्घटना है जिसमें इरादतन/ गैर इरादतन हत्या जैसी कोई बात नहीं है नाले नालियों से निकलने वाला कचरा सूखने के बाद तत्काल हटवा दिया था। स्वास्थ्य शाखा में संलग्न अधिकारी/ कर्मचारियों के लिखित कथन इसमें लगाएं है । इसके अलावा मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 27 मई को प्रकाशित सूचना के तथ्य पूर्णतः असत्य और भ्रामक लिखा है । दूसरी तरफ श्री पाण्डेय ने आवेदन पत्र पर राजनैतिक दुष्प्रेरणा की उत्प्रेरणा बताकर घटित अपराध पर संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपराधियों के प्रति संरक्षण का भाव और अपराध के प्रति समर्थन भाव त्यागकर थाना प्रभारी देहात को गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करने को या माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार बनना चाहेंगे लिखकर मामला और गरमा दिया।

कोई स्थाई नीति बनाकर

स्कूल के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें सरकार

- जिला कलेक्टर नरसिंहपुर और एसडीएम गाडरवारा को सौंपा ज्ञापन।

नरसिंहपुर। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति तथा अ. शि.संघ के जिला अध्यक्ष और प्रांत कार्यकर्ता एस.के. सोनी के आह्वान पर जिला मुख्यालय में कलेक्टर नरसिंहपुर एवं एसडीएम गाडरवारा को ज्ञापन सोपा गया।ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि स्कूल अतिथि शिक्षकों के लिए कोई स्थाई नीति बनाकर अधिकतम कार्य अनुभव कार्य दिवास के आधार पर सरकार भविष्य सुरक्षित करें।प्रदेश में विगत 15-16 वर्षों से 72000 से अधिक अतिथि शिक्षक अत्यंत कम मानदेय म पर सेवाएं देते आ रहे हैं।उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी दिया है ऐसे में इस शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य कोई काम करने की स्थिति में नहीं है परंतु स्कूल शिक्षा विभाग आधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से चाहे जब अनुभवी अतिथि शिक्षकों को भारी संख्या में बाहर कर दिया जाता है जिसके चलते वे रोजी-रोटी के लिए दर-दर भटकते है।इन सब के चलते विगत 02 से 04 वर्षों में लगभग 200 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है अथवा आकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं शेष अधिकांश के जीवन में मानसिक तनाव, क्लेश, अभाव बना हुआ है। ज्ञापन में याद दिलाया गया कि विधानसभा चुनाव के समय पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री का संपूर्ण मध्य प्रदेश में जगह-जगह फूल बरसा कर, दीपक जलाकर और ढोल नगाड़े पर आकर स्वागत किया गया था उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 23 को आतिथि शिक्षक की महापंचायत बुलाई थी लेकिन उनकी अभी तक घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। इससे अतिथि शिक्षक स्वयं ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आक्रोशित है।ज्ञापन में मांग की गई कि महा पंचायत की घोषणा के अनुसार अतिथि शिक्षकों की गुरु जी भांति विभागीय परीक्षा लेने और वर्तमान शिक्षक भर्ती 50 प्रतिशत आरक्षण ,वार्षिक अनुबन्ध और अधिकतम कार्य दिवसों के बोनस अंक जाने के आदेश शीघ्र जारी किया जावे।अतिथि शिक्षकों के नए पंजीयन के आदेश तुरंत निरस्त किए जाएं इसके स्थान पर जो ट्रांसफर ,पदोन्नति आदि के कारण अतिथि शिक्षक सेवा से बाहर हो गए हैं उन्हें अधिकतम अनुभव के आधार पर प्राथमिकता से पुनः सेवा में नियोजित किया जाए।

अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति सत्र के हिसाब से अधिकतम वर्षों के अनुभव के अंक जोड़े जाएं।स्कोरकार्ड में 2018 और 2023 की पूर्व पात्रता परीक्षा की भी जानकारी दर्ज की जाये ऐसी अन्य मांगो और समस्याओं के निराकरण के आदेश शीघ्र जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

यदि आदेश जारी नहीं होते तब 15 जून के बाद भोपाल में प्रान्त स्तर जन आंदोलन किया चेतावनी दी गई, जिला मुख्यालय नरसिंहपुर की टीम में, जिला अध्यक्ष एस के सोनी,बृजेन्द्र नेमा जिला उपाध्यक्ष,सचिन शर्मा नर ब्लाक अध्यक्ष,राजकुमारी मेहरा (जिला सचिव महिला मोर्चा) मुकेश कहार सहावन, अरुण पाठक, सुनील विश्कर्मा, राघवेंद्र पटेल, राकेश श्रीवास्तव,रोहित कौरव बरेली,रत्नेश मिढोतिया ,नीरज तिवारी,भूपेंद्र शर्मा, पंकज राजपूतइत्यादि पदाधिकारी एवं अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे एवं गाडरवारा एसडीएम को ज्ञापन सौपते समय ओमप्रकाश सोनी जिला कार्यकारणी सदस्य,सन्दीप कौरव भोरझिर जिला सचिव,

रामेश्वर मेहरा , सोहन पटेल, ललित नारायण गुर्जर,अर्पित गुप्ता ,अंकित रूसिया, आदित्य द्विवेदी , राहुल गुर्जर,रंजीत सराठे, अरविंद लोदी,अभिषेक कौरव इत्यादि पदाधिकारी व अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला

- मां, भाई के दोहरे हत्याकांड में दोहरा आजीवन कारावास

सुबह सवेरे सोहागपुर
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मां,भाई के दोहरे हत्याकांड के आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान माननीय द्वितीय अपर न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने आरोपी लीलाधर नागवंशी निवासी नवागांव को अपनी मां सानिया बाई और भाई विजय सिंह की हत्या करने का दोषी पाकर दोनों की हत्या करने पर दोहरा आजीवन कारावास की सजा एवं 5-5 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय दिया है। घटना के विवरण में एजीपी शंकरलाल मालवीय ने बताया 28. दिसंबर.21 की रात्री की है। ग्राम नवलगांव में मृतिका सनिया बाई अपने पुत्र विजय सिंह के साथ निवास करती थी। प्रातः 8 बजे मृतिका की पड़ोसी शशिवाई ने दोनों के शव अपने-अपने पलंग पर पड़े देखें ।दोनों के गले में साड़ी का फंदा लगा हुआ था। पुलिस ने मौके पर जाकर देहाती मर्ग एवं देहाती नालसी रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी। पुलिस को मृतिका के पास आरोपी की टोपी एवं सुसाइड नोट जौच करने में होवी भारोपी की होना एवं सुसाइड नोट मिला था। पुलिस ने मामले की जांच की । जिसमें सुसाइड नोट आरोपी के द्वारा लिखकर रखा गया था ।आरोपी की लिखावट की जाँच में यह प्रमाणित पाया गया कि आरोपी ने ही सुसाइड नोट लिखकर रखा गया था।आरोपी को घटना दिनाँक की रात्रि में 11 बजे सोहागपुर से घर तक आते हुए देखा गया था।सुबह 5 बजे घर से सोहागपुर तरफ जाते हुए ।गांव के स्वतंत्र साक्षियों ने देखा थाअभियोजन की ओर से आरोपी को फांसी की सजा से दंडित करने का निवेदन किया गया था। न्यायालय के द्वारा विलरतम अपराध मानते हुए। आरोपी लीलाधर नागवंशी को अपनी मां सनिया बाई एवं भाई विजय की हत्या करने का दोषी पाकर दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता शंकर लाल मालवीय ने की थी । आरोपी को सजा भुगतने हेतु उपजेल पिपरिया भेजा गया ।

परिवर्तन किए जाने का एनएसयूआई ने विरोध किया

नरसिंहपुर। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम परिवर्तन किए जाने का एन एस यू आई ने विरोध किया है। इसे लेकर एन एस यू आई ने बुधवार को विरोध प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष ईशान राय ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में स्थित जिले के सबसे बड़े एवं प्राचीन उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर उसे पीएम श्री पीजी कॉलेज किया जा रहा है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कर

आवश्यक कागजी कार्रवाई की जा चुकी है। जिसका भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पुरजोर विरोध करता है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्षों से जो संस्थान जिस नाम से संचालित है, उस नाम में पीएम श्री जाकर क्यों जोड़ा जा रहा है। यदि सुविधाओं के इजाफे की बात है तो वह सुविधा अब भी दी जा सकती हैं। सरकार को चाहिए कि वह नाम परिवर्तन किए बिना सुविधाओं का विस्तार और छात्र-छात्राओं की मांगों को पूरा करे। एनएसयूआई की मांग है कि इस नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए। ऐसा न होने पर संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उक्त मौके पर एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक पटेल, जिला महासचिव युवा कांग्रेस शिवम पाठक, निकिता सक्सेना, आरिफ खान, देवेंद्र पटेल, सत्यम ठाकुर, विनय प्रजापति, अंकित राय, राहुल दुबे, मोहित ठाकुर, राहुल तिवारी, आकाश श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उड़नदस्ता गठित

नरसिंहपुर। मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2024 की परीक्षा 23 जून को प्रात- 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एंव दोपहर 2.15 बजे से 4.15 बजे तक दो सत्रों में आयोजित की जायेगी। अपर कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी नरसिंहपुर ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उड़नदस्ता गठित किया है। उक्त उड़नदस्ता परीक्षा केन्द्रों का संघन निरीक्षण कर सतत निगरानी बनाये रखेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस कार्य के लिए अधिकृत अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर अपने स्तर से भी ड्यूटी लगा सकेंगे। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला महाविद्यालय नरसिंहपुरा, शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला नरसिंहपुर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला नरसिंहपुर, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नरसिंहपुर व शासकीय पीजी कॉलेज नरसिंहपुर को परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर व राजस्व निरीक्षक नरसिंहपुर श्री विनीत साहू को कार्यपालिक दंडाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन सहभागिता की अनूठी पहल

नरसिंहपुर। राज्य शासन की मंशानुसार जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों का संचालन नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार किया जा रहा है। इस दौरान शासकीय अमला, सामाजिक संस्था, जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों की जनभागीदारी से अभियान को संचालित करने में सहयोग मिल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपनी दैनिक जीवनशैली में छोटे- छोटे बदलाव लाकर पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खेत- तालाब योजना के माध्यम से पानी को सहेजने के साथ- साथ करेंगे मछली पालन का कार्य

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले की चीचली विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महगवां (कला) में हितग्राही कलावती स्वयं के खेत में 3.06 लाख रुपये लागत के खेत- तालाब का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जा रहा है। वे कहती हैं कि खेत- तालाब योजना के माध्यम से तालाब बन जाने से पानी को सहेजा जा सकेगा। वे इस तालाब में मछली का पालन भी करेंगी।

शासकीय भूमि में बन रहा डगपांड

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से बरसात के पूर्व जिले की ग्राम मगरमुहा- दिघौरी में शासकीय भूमि पर निस्तारी उपयोग के लिए मनरेगा योजना के माध्यम से 4.32 लाख की लागत सामुदायिक डगपांड का निर्माण किया जा रहा है। इसके बन जाने से ग्रामवासियों को पानी आसानी से उपलब्ध होगा। इसके साथ- साथ पशु- पक्षियों को भी सहजता से पानी मिलेगा। ग्रामवासियों ने जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रशंसा की।

ग्राम पंचायत बिछुआ की ग्राम सर्रा में बौल्डर चैक निर्माण: जल को सहेजने और बरसात के पूर्व भूमि के जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से पौधरोपण, स्वच्छता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत बिछुआ की ग्राम सर्रा में बौल्डर चैक निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत इमलिया में बन रहा परकोलेशन टैंक: जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने के लिए उद्देश्य से जिले में बड़े पैमाने पर कार्य किये जा रहे हैं। जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत इमलिया के ग्राम सगोनी में परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके बन जाने से बरसात के पानी को संरक्षित कर सकेंगे।

जनसहयोग से हो रहा जल बचाने का कार्य: जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनसहयोग से जल संरक्षण की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। इसी प्रकार जिले की चांवरपाठा विकासखंड के ग्राम करहैया- कोरई में डगपॉड का निर्माण, ग्राम सासबहु में तालाब जीर्णोद्वार और ग्राम पंचायत बसेड़ी में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है।

ओशो धाम आश्रम की हुई साफ- सफाई व जीर्णोद्धार: नगर पालिका परिषद गाडरवारा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ओशो धाम आश्रम गाडरवारा में साफ- सफाई व जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। इसमें सभी अधिकारी- कर्मचारियों ने भाग लिया।

भिंड में दूषित पानी पीने से 3 की मौत

- 70 से ज्यादा बीमार, 2 घंटे में 9 एंबुलेंस बुलानी पड़ी; जल प्रदाय प्रभारी सस्पेंड

भिंड (नप्र)। भिंड के फूप में नल से आ रहा बदबूदार दूषित पानी पीने से हर दूसरे घर में कोई न कोई बीमार है। लोगों को उल्टी - दस्त हो रहे हैं। सोमवार रात तक मरीजों की संख्या 52 थी, मंगलवार रात तक 24 और नए मरीज सामने आ गए। 3 दिन में वार्ड 5, 6 और 7 में 2 बुजुर्गों और 1 लड़की की मौत हो चुकी है। 76 लोग बीमार हैं। परिजन का कहना है कि दूषित पानी पीने के बाद उल्टी-दस्त हुए और मौत हो गई। हालात इतने बदतर हैं कि मंगलवार की शाम 6.30 बजे से रात 8.30 बजे के बीच 2 घंटे में 108 एंबुलेंस की 9 गाड़ियां बुलवाकर 9 मरीजों को ग्वालियर रेफर कराना पड़ा है। अब तक कुल 20 मरीजों को ग्वालियर रेफर करने की बात सामने आई है। मुरैना और ग्वालियर से 6 एंबुलेंस और बुलाकर भिंड जिला अस्पताल में खड़ा कराया गया है। 3 एंबुलेंस को फूप में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उधर, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ. अवधेश सोनी दूषित पानी पीने से मौत होने की बात को पूरी तरह नकार रहे है। वे दो बुजुर्गों की मौत का कारण उनकी पुरानी बीमारी को बता रहे हैं।

कलेक्टर से लोगों ने की बहस

भिंड कलेक्टर संदीप श्रीवास्तव बुधवार सुबह फूप पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों की कलेक्टर से बहस भी हो गई। कलेक्टर ने नगर पंचायत के जल प्रदाय प्रभारी नीरू बघेल को निलंबित कर दिया है। फोन रिसीव नहीं करने पर पटवारी ब्रजमोहन को भी सस्पेंड किया है।

भोपाल में डिपो के टैंकर से पेट्रोल-डीजल चोरी

- एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ड्राइवर-कंडक्टर को पकड़ा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के भौंरी बकानिया स्थित रिलायंस एवं भारत पेट्रोलियम डिपो से निकलने वाले टैंकरों से डीजल-पेट्रोल चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां स्थित ढाबों पर इन टैंकरों से डीजल-पेट्रोल चोरी किया जाता है। सोमवार को पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टैंकरों से पेट्रोलियम चोरी करते हुए ड्राइवर और कंडक्टर को रंगे हाथों पकड़ा है। ये बड़े पेचकस या सब्बल से टैंक के ताले को सरका कर कैन में डीजल-पेट्रोल निकाल लेते हैं। इसके बाद ताला वापस वैसा ही कर दिया जाता है। जब इन्हें रंगेहाथों पकड़ा गया तो ढाबे वालों ने विवाद भी किया। इस संबंध में खजूरी सड़क थाने में शिकायत की गई है।

वीडियो बनाने लगे तो धमकाया

पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह ने बताया कि भौरी बकानिया स्थित रिलायस और भारत पेट्रोलियम डिपो से आसपास के जिलों में टैंकरों से पेट्रोल-डीजल भेजा जाता है। डिपो से गाड़ियां भरने के बाद मुख्य द्वार के बाहर आसपास ढाबों-होटलों पर तेल माफियाडीजल-पेट्रोल चोरी करते हैं। सोमवार को एक टैंकर रिलायंस डिपो से होशंगाबाद के लिए निकला था। इस टैंकर से डीजल-पेट्रोल चोरी की जा रही थी। होशंगाबाद डीलर फौजदार ने टैंकर से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। जैसे ही इसका वीडियो बनाने लगे तो माफियाओं के गुंडों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।

डॉ. राजेश राजौरा बने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव

- संजय शुक्ला सीएमओ में प्रमुख सचिव; रश्मि शमी को विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन बनाया

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा को अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। वे पूर्व में दिए गए दायित्व भी निभाते रहेंगे।

वहीं, महिला और बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला को प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा मंगलवार देर रात जारी आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को विशेष आयुक्त, समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली और आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव की पहली पदस्थापना: मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के रूप में पदस्थापना का यह पहला मामला है। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सीएम ऑफिस में दो से तीन प्रमुख सचिव रहे हैं लेकिन अपर मुख्य सचिव के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया था।

अब सीएमओ में मुख्य सचिव के साथ दो अपर मुख्य सचिव: डॉ. राजेश राजौरा की सीएम ऑफिस में एसीएस के रूप में पदस्थापना के बाद अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वे नए मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे हैं। राघवेंद्र सिंह पहले से ही सीएम ऑफिस में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव के साथ दो अपर मुख्य सचिव हो गए हैं।

14 जून से 5 दिवसीय आम महोत्सव

शुगर मरीजों के लिए सुरक्षित 'सुंदरजा' भी मिलेगा; 18 टन आम आएंगे भोपाल

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 14 जून से पांच दिवसीय आम महोत्सव शुरू होने जा रहा है। आम की कई नई वैराइटी भी देखने को मिलेंगी। इसमें शहडोल का आम्रपाली और मल्लिका के अलावा सतना का सुंदरजा आम भी शामिल है। यह आम प्रदर्शनी व सेल बिट्टन मार्केट स्थित नाबार्ड कार्यालय में रहेगी। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बताया, इस बार आम महोत्सव 14 से 18 जून तक रहेगा। इसका उद्देश्य यही है कि आदिवासियों को हम बाजार उपलब्ध कराएं। इस वर्ष आम महोत्सव का आठवां संस्करण है। 11 जिलों से विक्रेता आएंगे, इसमें नर्मदापुरम, अलीराजपुर, रीवा, छिंदवाड़ा और झाबुआ शामिल है। पिछले बार इन जिलों से करीब 10 टन आम लाए गए थे वहीं इस सीजन करीब 18 टन आम आने की संभावना है।

शुगर मरीजों के लिए खास सुंदरजा आम

सुनील कुमार कहते हैं कि इस वर्ष आम महोत्सव में खास नूरजहां और सुंदरजा आम रहेंगे। सुंदरजा आम की बात की जाए तो यह एक जीआई टैग आम है। इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, इसकी अपनी कई तरह की खूबियां होती हैं, यह आम शुगर मरीजों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा हर बार की

तरह इस बार भी नूरजहां प्रदर्शनी के लिए आएगा, इस आम की खासियत यह है कि यह आम दो से तीन किलो का होता है, इसका छिलका काफी पतला होता है वहीं इसकी गुठली भी बहुत छोटी होती है।

बिना केमिकल के भूसे में रखकर पकाए आम: नाबार्ड के अधिकारियों के अनुसार इस आम महोत्सव में जो आम आएंगे उनकी कीमत सामान्य बाजार में बिकने वाले आमों से 10 से 20 प्रतिशत ज्यादा होगी। इसके कारण यह है कि इन्हें किसी भी प्रकार के केमिकल से नहीं पकाते। इन्हें पकाने के लिए भूसे के अलावा कागज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, कई वैराइटी ऐसी भी हैं, जो कि प्राकृतिक तौर पर पेड़ पर ही पकाई जाती हैं। बता दें कि इस मेले में विभिन्न किस्मों जैसे सुंदरजा, केसर, चौंसा, लंगड़ा व दशहरी आम उपलब्ध रहेगा।

साल भर पहले सुरंदजा को मिला जीआई टैग: देश-विदेश में विंध्य को पहचान दिलाने वाले सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल गया है। बताया गया कि रीवा में 237 वैरायटी वाले आम के बागान है। पर सबसे खास गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन कृषि महा विद्यालय का फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया 32 हेक्टेयर में फैला है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उपक्रम है। दावा है कि रीवा के फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में आम और अमरूद पर रिसर्च की जाती है। फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया के वैज्ञानिक डॉ टीके सिंह द्वारा कुछ वर्ष पहले जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था। जिसको स्वीकार कर सुंदरजा आम को टैग दे दिया गया है।

सज्जन वर्मा बोले-इंदौर-भोपाल में भयानक बिजली कटौती

ऊर्जा मंत्री का तर्क-क्षमता से ज्यादा लोड होगा तो ट्रांसफॉर्मर जलेंगे, ये अवरोध है.. कटौती नहीं

भोपाल (नप्र)। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश में भारी बिजली संकट होने का दावा कर कहा कि बिजली कटौती के कारण परेशान हैं। मप्र में बिजली का भयानक संकट है। इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा- लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर जल रहे हैं, यह अवरोध होता है, बिजली कटौती नहीं।

सज्जन बोले- शहरों में 10-10 बार अघोषित कटौती

पीसीसी में मीडिया से चर्चा में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- भीषण गर्मी के दौर में प्रदेश के दूरस्थ गांवों से लेकर राजधानी भोपाल में लोग बिजली कटौती के कारण परेशान हैं। इंदौर-भोपाल जैसे शहरों में 10-10 बार अघोषित कटौती हो रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- मोहन यादव ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उस रिपोर्ट कार्ड में इन बातों का कहीं जिक्र नहीं हैं। स्वायत्त संस्थाओं में सरकार की नाक के नीचे मंत्रालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जनता देख रही है। जनता समझती थी कि कोई नया चमत्कार होगा। लेकिन, चमत्कार की जगह आम जनता का और ज्यादा नुकसान हो रहा है। मोहन यादव के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड फ्रॉड मानता हूं। ये रिपोर्ट कार्ड सही नहीं हैं। हर तरफ अराजकता है।

ऊर्जा मंत्री बोले- यह विद्युत अवरोध है, कटौती नहीं: इधर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है

कि- हमारे प्रदेश में बिजली सर प्लस है। बिजली की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि, जैसे टेंप्रेचर ज्यादा हुआ। किसी क्षेत्र में बिजली की मांग 70 किलोवॉट की है और वहां ट्रांसफॉर्मर 100 किलोवॉट का लगा है। वहां मांग सिर्फ 70 किलोवॉट की थी। हमने 30 किलो वाट ज्यादा का ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। लेकिन, ट्रांसफॉर्मर पर यदि 200 किलोवॉट का लोड आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर जलेगा या ट्रिप करेगा। ऐसी स्थिति में लाइट बंद होगी। यह विद्युत अवरोध है, कटौती नहीं। विकास के लिए रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं। लाइन शिफ्ट होगी तो अवरोध होगा। हमारे यहां बिजली की कोई कमी नहीं है।

मेंटेनेंस आदिकाल से होता आ रहा है

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा- मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप अपनी गाड़ी को ही ले लीजिए। एक निश्चित किलोमीटर के बाद उसकी सर्विस होती है। ऐसे ही बिजली के ट्रांसफॉर्मर में उनका तेल चेक होना, वायर में कहीं कार्बन तो जमा नहीं हो गया। ऐसे मेंटेनेंस के लिए भी बिजली अवरुद्ध की जाती है। मेंटेनेंस के नाम पर कटौती नहीं होती। यह मेंटेनेंस आज से नहीं आदिकाल से हो रहा है।

एमपी में 20-21 प्रतिशत लाइन लॉस

ऊर्जा मंत्री ने कहा- लाइन लॉस को रोकने के लिए तमाम योजनाएं चल रही है। (आईआईआईडीएस) के तहत मध्य प्रदेश में पहले से काफी लाइन लास कम किया है। आज मध्य प्रदेश में 20-21 प्रतिशत लाइन लॉसेस है। निरंतर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

छिंदवाड़ा-सिवनी,मंडला-बालाघाट में आज आंधी-बारिश

- *एमपी में प्री-मानसून एक्टिविटी; निवाड़ी, टीकमगढ़-सिंगरौली में गर्म हवा भी चलेगी*

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में प्री-मानसून एक्टिविटी जारी हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ), साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आंधी, बारिश का दौर है। मंगलवार को धार में तेज बारिश हुई, जबकि 10 से ज्यादा जिलों में आंधी चली। बुधवार को भी आंधी-बारिश होने का अनुमान है। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी ओर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सिंगरौली में गर्म हवाएं चल रही हैं।

बुधवार को श्योपुरकलां, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और अनूपपुर में आंधी, गरज-चमक की स्थिति भी रहेगी।

प्रदेश में दो तरह का मौसम

मंगलवार को प्रदेश में दो तरह का मौसम देखने को मिला। दोपहर में धार में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं, रतलाम, झाबुआ, आगर, बैतूल, आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, बालाघाट, उज्जैन, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, इंदौर, मंडला, डिंडोरी में भी मौसम बदला रहा। इससे पहले कई शहरों में गर्मी का असर भी रहा।

सबसे गर्म रीवा रहा। यहां दिन का टेम्प्रेचर 44.6 डिग्री रहा। प्रदेश के टॉप-10 सबसे ज्यादा तापमान वाले शहर में सिंगरौली, सीधी, सतना, ग्वालियर, शहडोल, खजुराहो, शिवपुरी, जबलपुर और उमरिया शामिल हैं। सिंगरौली में 44.3 डिग्री, सीधी में 44 डिग्री, सतना में 43.3 डिग्री, ग्वालियर में 42.8 डिग्री, शहडोल में 42.4 डिग्री, खजुराहो में 41.4 डिग्री, शिवपुरी में 41 डिग्री, जबलपुर में 40.7 डिग्री और उमरिया में 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

बड़े शहरों में भोपाल में 39.3 डिग्री, इंदौर में 36.6 डिग्री, ग्वालियर में 42.8 डिग्री, जबलपुर में 40.7 डिग्री और उज्जैन में पारा 37.8 डिग्री दर्ज किया गया।

एक-दो दिन देर से आएगा मानसून

भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्री-मानसून एक्टिविटी है।

स्कूल शिक्षा विभाग कराएगा शिक्षकों का वेरिफिकेशन

प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों की विभाग से खत्म होगी पदस्थापना

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जो शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में चले जाएंगे उनकी पदस्थापना विभाग में खत्म कर दी जाएगी। उनके स्थान पर विभाग नए शिक्षक की पद स्थापना करेगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे पदों की स्थिति का वेरिफिकेशन कराकर उसे विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जारी आदेश में कहा है कि प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों के पदनाम के आगे स्टाप पेमेंट परमानेंट दर्ज किया जाए। इस निर्देश में यह स्पष्ट नहीं है कि जब संबंधित शिक्षक प्रतिनियुक्ति से वापस होने पर अपने मूल विभाग में पद स्थापना के लिए लौटेगा तो उसे कैसे विभाग में एडजस्ट किया जाएगा।

हर टीचर का होगा वेरिफिकेशन

विभाग ने कहा है कि संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी हर विद्यालय में पदस्थ शिक्षक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं। इस वेरिफिकेशन के लिए सभी विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के नाम और अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड भी की गई है। इसमें यह भी कहा है कि सभी शिक्षकों की आईडी पर उनकी ई पुस्तिका प्रदर्शित होती है। इसलिए इसका प्रचार प्रसार कर शिक्षकों से उनकी

पदस्थापना संबंधी जानकारी वेरिफाई कराई जाए और संशोधन हो तो परीक्षण कराकर संशोधन कराया जाए।

उच्च पद के प्रभार का करें अपडेशन

विभाग के निर्देश में यह भी कहा है कि उच्च पद का प्रभार दिए जाने के मामले में भी वेरिफिकेशन किया जाना है। जिनके आदेश ऑनलाइन जनरेट हुए थे, और जिनके आफ लाइन या मैन्युअल आदेश जनरेट हुए हैं उनका अपडेशन करने की सुविधा संभागीय संयुक्त संचालक के लॉगिन पर दी गई है। यह प्रक्रिया 13 जून तक पूरी करने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि अगर कोई टीचर इनेक्टिव है तो उस टीचर का ई-केवाईसी कराया जाए और जिला शिक्षा अधिकारी के परीक्षण के बाद पोर्टल में नाम दर्ज किया जाए।

उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 14 जून से अपलोड होंगे दस्तावेज: इधर, एक अन्य आदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई गई उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के लिए चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल पंजीयन और शाला विकल्प के लिए 14 जून से 18 जून तक तारीख तय की गई है। इसके बाद जिला स्तर पर 21 जून से 23 जून के बीच दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

भोपाल में दिनदहाड़े व्यापारी के घर में घुसे बदमाश

- पिस्टल अड़ाकर करने लगे लूट, बच्चे ने शोर मचाया तो भाग निकले

भोपाल (नप्र)। राजधानी के पिपलानी इलाके में मंगलवार दोपहर 4 बदमाश एक व्यापारी के घर में घुस गए। बदमाशों ने यहां व्यापारी को पिस्टल अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तभी व्यापारी के बेटे के शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए। व्यापारी ने घटना की शिकायत पिपलानी थाना पुलिस को की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में मनीष तनवानी रहते हैं। मनीष तनवानी की भेल क्षेत्र स्थित गांधी मार्केट में चश्मे की दुकान है। वे मंगलवार शाम 4 बजे अपने घर पौधों में पानी डालने गए थे। तभी मकान के मैन गेट का ताला तोड़ते तीन बदमाश दिखाई दिए। इस पर मनीष तनवानी ने जब बदमाशों से मकान का ताला तोड़ने के बारे में पूछा, तो बदमाशों ने पिस्टल अड़ा दी। साथ ही घर के अंदर ले जाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तभी घर में मौजूद मनीष तनवानी के बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे घबराकर बदमाश लूट का सामान लिए बगैर व्यापारी के घर से भाग गए।

व्यापारी के घर कार से पहुंचे थे बदमाश: पिपलानी थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चश्मा कारोबारी मनीष तनवानी के घर में घुसे बदमाश, उनके घर तक सफेद रंग की लग्जरी कार से पहुंचे थे। व्यापारी के बेटे के शोर करने पर तीनों बदमाश मौका पाकर लूट का सामान छोड़कर मौके से फरार हो गए।